



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2009/भाद्र 16, 1931

No. 292]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2009/BHADRA 16, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय: चीन जन. गण. तथा इजराइल के मूल के या वहां से निर्यातित सिंक्रोनस डिजिटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण के आयात के बारे में पाटनरोधी जांच ।

फा. सं. 14/2/2009-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए

2. यतः मै. तेजस नेटवर्क्स लि. (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने चीन जन. गण. एवं इजरायल (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सिंक्रोनस डिजिटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए अधिनियम एवं नियम के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और जांच शुरू करने तथा संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

3. और यतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने, जिस यदि लागू किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए नियम 5(5) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में जांच शुरू करते हुए दिनांक 21 अप्रैल, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

प्रक्रिया

4. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरुआत को अधिसूचित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद इस जांच के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है ।

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 21 अप्रैल, 2009 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत स्थित संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/प्रतिनिधियों, संबद्ध देशों/क्षेत्रों के ज्ञात निर्यातकों, आयातकों एवं घरेलू उद्योग को भेजीं और उनसे जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिन के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने और अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया ।
- (ii) उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के अगोपनीय रूपांतरण की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों एवं संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों/उच्चायोगों को उपलब्ध कराई ।
- (iii) नियम 6(2) के अनुसार नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों को जांच की शुरुआत के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वे निर्धारित अवधि के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों/क्षेत्रों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें । पत्र, निर्यातक को भेजी गई याचिका तथा निर्यातक प्रश्नावली के अगोपनीय रूपांतरण भी याचिकाकर्ताओं द्वारा ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की उपलब्ध कराई गई सूची के साथ भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों को भेजी गई थी ।
- (iv) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए संबद्ध देशों में संबद्ध उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी ।
 1. हुआवी टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
 2. वुहान रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड टेली कम्युनिकेशन
 3. जैडटीई कार्पोरेशन
 4. ई सी आई टेलीकॉम
- (v) उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों ने प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर किए:
 1. जैडटीई कार्पोरेशन लि.
 2. हुआवी टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
 3. शेनजेन हुआवी टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
 4. हीसिलिकॉन टेक्नोलॉजीज लि.
 5. फाइबर होम टेलीकम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
 6. वुहान फाइबर होम इंटरनेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.
 7. हेंगझाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन्स कंपनी लि.
 8. ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन्स कंपनी लि.

9. अल्काटेल लूसेंट शंघाई बेल कंपनी लि.

- (vi) इसके अलावा, चीन के मशीनरी एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आयात व निर्यात वाणिज्य मंडल "सी सी सी एम ई" ने भी एक अभ्यावेदन दायर किया है जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है।
- (vii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थीं।
- | | |
|---|-----------------------------------|
| एअरसेल लिमिटेड | पृथ्वी इनफॉर्मेशन लि. |
| डिसनेट वायरलैस लिमिटेड | पंजाब कम्यूनिकेशन्स लि. |
| भारती एयरटेल लिमिटेड | एचटीएल जीएचटी |
| भारत संचार निगम लिमिटेड | हुवाई इंडिया |
| टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड | जैट टी ई इंडिया |
| टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड | ई सी आई इंडिया |
| आइडिया सेल्युलर लिमिटेड | अल्काटेल लूसेंट |
| वोडाफोन एस्सार लिमिटेड | नोकिया सीमेंस नेटवर्क |
| रेलटेल कार्पो. ऑफ इंडिया लिमिटेड | एरीक्शन |
| टाटा कम्यूनिकेशन्स | हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स |
| रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | आई सी ओ एम एम |
| श्यान टेलीलिक्स | |
- (viii) निम्नलिखित ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
1. ई सी आई इंडिया प्रा. कं. लि.
 2. हुवाई इंडिया टेलीकम्यूनिकेशन प्रा.लि.
 3. वोडाफोन एस्सार लि.
 4. बुप्पालामृता मैग्नेटिक कंपोनेंट्स लि.
 5. पृथ्वी इनफॉर्मेशन सॉल्यूशन्स लि.
- (ix) इसके अलावा, मामले के विभिन्न पहलुओं पर ई सी आई की ओर से ई एल पी द्वारा और एअरसेल की ओर से लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन ने भी अनुरोध किए हैं, तथापि, ये अनुरोध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अंतिम अनुमत्य विस्तारित तारीख के लगभग दो माह बाद किए गए हैं और इसलिए इन पर प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया गया है।
- (x) जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के व्यौरों की व्यवस्था करने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से अनुरोध किया गया था ;
- (xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षणार्थ खुला रखा;

- (xii) विचारकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत अनंतिम रूप से निकाली गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ;
- (xiii) विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में उनकी गोपनीयता के दावों की जांच की गई है । हितबद्ध पार्टियों द्वारा ऐसी सूचना जिसकी प्रकृति गोपनीय है अथवा जिसे अगोपनीय सारांश के साथ गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है, को इस जांच परिणाम में गोपनीय (***) माना गया है जो गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।
- (xiv) यह जांच 1 अप्रैल- 31 दिसंबर, 2008 (9 माह-जांच अवधि) तक की अवधि के लिए की गई थी और क्षति की जांच 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा जांच अवधि के लिए की गई थी ।
- (xv) एस डी एच उपकरण की बिक्री सामान्यतः नगों में की जाती है । तथापि, इसका आयात संयोजित उत्पाद के रूप में या सी के डी/एस के डी स्थितियों में किया जा सकता है । अलग-अलग एस डी एच उपकरणों की संबद्ध लागत एवं कीमत में अंतर होता है ।

विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "संयोजित रूप में, सी के डी, एस के डी रूप में आकस्मिक ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण से फिट किए गए सिंक्रोनस डिजीटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण, उसके पुर्जे, संबद्ध सॉफ्टवेयर तथा उसके आवश्यक पुर्जे एवं संघटक" हैं ।
6. एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों को मल्टीप्लेक्सर, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर (ए डी एम), मल्टीप्लेक्सर, एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, (एम ए डी एम), डिजीटल क्रॉस-कनेक्ट, पापुलेटेड पी सी बी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेसेज तथा एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के लिए निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरणों के आवश्यक पुर्जे शामिल होते हैं और ये विचाराधीन उत्पाद के दायरे में हैं बशर्ते उक्त संघटक केवल एस डी एस ट्रांसमिशन उपकरण के लिए निर्दिष्ट हों ।
7. एस डी एस ट्रांसमिशन उपकरणों की खरीद ट्रांसमिशन उपकरणों के रूप में या अन्य उपकरण के भाग के रूप में अर्थात् ब्रॉड बैंड और/अथवा सेल्युलर (जीएसएम एवं सी डी एम ए दोनों) उपकरणों के रूप में की जा सकती है । ब्रॉड बैंड और/अथवा सेल्युलर उपकरण के भाग स्वरूप एस डी एस ट्रांसमिशन उपकरण भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं ।

8. विचाराधीन उत्पाद अनिवार्य अनेक इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और/अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड सर्किट बोर्डों का संयोजन है जिसे संयुक्त कम गति के सिग्नलों को अल्प या लंबी दूरी में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पारेषण हेतु उच्च गति के सिग्नलों में मल्टीप्लेक्सिंग हेतु नियम कार्यों के निष्पादन हेतु तैयार किया जाता है। चूंकि अन्य अनुप्रयोगों में इन्हें बेश ट्रान्समिशन केन्द्रों, स्विच एक्सचेंजों तथा मौजूदगी के अन्य केन्द्रों पर स्थापित किया जाता है, इसलिए अलग-अलग स्थानों पर स्थापित एस डी एच उपकरण संबद्ध गुणधर्मों के संबंध में अलग-अलग हो सकते हैं। अलग-अलग एस डी एच उपकरण भौतिक एवं ऑप्टिकल, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, आर एंड डी विकास, सॉफ्टवेयर क्षमताओं, कार्य एवं उपयोग आदि सहित उत्पाद की अनिवार्य विशेषताओं के संबंध में तुलनीय हैं। तदनुसार विभिन्न एस डी एच उपकरणों को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ एक समान उत्पाद माना गया है।

9. विचाराधीन उत्पाद का आयात पूर्ण उपकरण के रूप में या सी के डी, एस के डी रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, नेटवर्क में जोड़ने/एस डी एच ट्रान्समिशन उपकरण की स्थापना करने के लिए कई सहायक उपकरणों की जरूरत होती है (ई-1 केबल, पी सी एम केबल, पॉवर केबल, रैक, वर्क स्टेशन आदि)। सॉफ्टवेयर इन उपकरणों का अभिन्न अंग होता है जिसे उपकरण के भाग के रूप में या अलग से खरीदा जा सकता है। ये सभी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।

10. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु अनंक्त संघटकों की जरूरत होती है जिनके बहु-विकल्पीय उपयोग होते हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि संघटकों के संबंध में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल ऐसे संघटकों और पुर्जों तक सीमित है, जिनका विचाराधीन उत्पाद के बारे में ही अनन्य रूप से उपयोग होता है। दूसरे शब्दों में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल उन संघटकों/पुर्जों पर लागू होता है, यदि उनका अनन्य रूप से उपयोग एच डी एच उपकरण के उत्पादन में होता हो।

11. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकृत है। भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-1 के शीर्ष 851762 के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग का आधार घरेलू उद्योग के अनुरोध

12. याचिकाकर्ता ने वॉयस एवं डॉटा रिकार्डर मैग्जीन में प्रकाशित सूचना के आधार पर अन्य भारतीय उत्पादकों का उत्पादन निर्धारित किया है जिसे संबंधित उत्पाद हेतु सूचना के निर्धारण हेतु उचित ढंग से समायोजित किया गया है।

13. इस याचिका का मै. मेजरमेंट एंड कंट्रोल्ल्स लि. ने समर्थन किया था।

14. याचिकाकर्ता का उत्पादन संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है । याचिकाकर्ता नियमानुसार आधार की अपेक्षा की पूर्ति करता है ।

15. सी एमए आई के पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है ।

16. इस बात के होते हुए भी कि उनके द्वारा संघटकों या उप संयोजनों का पूरक आयात किया जा रहा है, याचिकाकर्ता पर वर्तमान याचिका दायर करने हेतु पात्र घरेलू विनिर्माता के रूप में विचार किया जाना चाहिए;

17. अन्य कंपनियां भारत में केवल वृद्धिकारी कार्यकलाप कर रही हैं और वे इन कारणों से अपात्र घरेलू विनिर्माता हैं (i) वे निविष्टि का उत्पादन में पर्याप्त रूपांतरण करने के लिए भारत में उत्पादन कार्यकलाप पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रही हैं, (ii) इन कंपनियों को हर हालत में अपात्र माना जाए क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त आयात कर रही हैं और/अथवा वे सबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के विदेशी आयातकों से संबद्ध हैं । इन कंपनियों का मुख्य ध्यान भारत में पूरक संयोजन लाइन के आयात या जांच संबंधी प्रचालनों पर केन्द्रित होता है ।

18. भारतीय बाजार में एस डी एच उपकरणों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

क. ऐसी कंपनियां जो भारत में प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण सहित पूर्ण उत्पाद जीवन चक्र से संबंधित व्यय करती हैं ।

ख. ऐसी कंपनियां जो भारत से बाहर प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण सहित प्रमुख उत्पाद संबंधी व्यय करती हैं और अंतिम संयोजन/जांच संबंधी अनुदेशों के साथ तैयार उत्पाद का भारत को निर्यात संयोजित रूप में या सी के डी/एस के डी स्थिति में करती हैं ।

19. जांच अवधि के दौरान तेजस द्वारा सामग्री की खपत का विभाजन का पता निम्नलिखित तालिका से चलता है :

वित्तीय नग करोड़ में	कुल मूल्य	%
बिक्रीत वस्तु का मूल्य (सी ओ जी एस)	***	
आर एंड डी पर व्यय	***	***
खपत की गई कच्ची सामग्री	***	***
विनिर्माण संबंधी ऊपरी व्यय	***	***
एस जी एंड ए तथा अन्य व्यय	***	***
खरीदी गई कुल कच्ची सामग्री	***	***
खरीदी गई घरेलू कच्ची सामग्री	***	***

खरीदी गई आयातित कच्ची सामग्री	***	***
कच्ची सामग्री संबंधी टूट-फूट		
<input type="checkbox"/> आयातित कच्ची सामग्री	***	***
<input type="checkbox"/> चीन से	***	***
<input type="checkbox"/> इजराइल से	***	***
<input type="checkbox"/> अन्य देशों से	***	***
लगाई गई पूंजी		
<input type="checkbox"/> निवल नियत	***	
परिसंपत्तियां		
<input type="checkbox"/> आर एंड डी में लगाई गई	***	***
निवल नियत परिसंपत्तियां		
<input type="checkbox"/> निवल नियत	***	***
परिसंपत्तियां अन्य पूंजी		

20. देश-वार खरीद को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है :

स्थान	राशि	कुल खरीद का %
थाइलैंड	***	***
भारत	***	***
सिंगापुर	***	***
चीन	***	***
ताइवान	***	***
जापान	***	***
हांगकांग	***	***
अमरीका	***	***
यूनाइटेड किंगडम	***	***
स्विटजरलैंड	***	***
इजराइल	***	***
दुबई	***	***
कनाडा	***	***
मलेशिया	***	***
जर्मनी	***	***
फिलीपिन्स	***	***
फ्रांस	***	***
महा योग	***	

खरीद संबंधी विश्लेषण

कुल घरेलू मूल्य	874,261,252	34.42%
आयातों का कुल मूल्य	1,665,890,195	65.58%
	2,540,151,447	

21. यह देखा जा सकेगा कि जहां कच्ची सामग्री का मूल्य कुल उत्पादन लागत का ***% है वहीं याचिकाकर्ता द्वारा आयातित चीन के पुर्जों/संघटकों का मूल्य कच्ची सामग्री की कुल खरीद का केवल ***% (अर्थात् कुल लागत का केवल ***%) है ।

22. निम्नलिखित तालिका से चीन से आयातित पुर्जों/संघटकों की टूटफूट का पता चलता है :

वस्तु	कुल (रुपए)	कुल खरीद का %	कुल उत्पादन लागत का %
ट्रांसीवर्स	***	***	***
बेयरबोर्ड	***	***	***
पेच कॉड	***	***	***
विषिध	***	***	***
पी सी बी ए (अन्य मद से निर्मित)	***	***	***
कैपेसिटर	***	***	***
कनेक्टर	***	***	***
महायोग	***		***

23. प्रिंटेड सर्किट बोर्डों को छोड़कर चीन से आयातित पुर्जों/संघटक ऐसे पुर्जों/संघटक हैं जिनका अनन्य उपयोग विचाराधीन उत्पाद में नहीं होता है । जहां तक प्रिंटेड सर्किट बोर्डों का संबंध है, न केवल आयात मूल्य काफी अधिक है, अपितु इनका उत्पादन भी याचिकाकर्ता की प्रौद्योगिकी के अनुसार किया गया है ।

24. निम्नलिखित तालिका से तेजस के विनिर्माण प्रचालन कार्यकलापों के वित्तीय ब्यौरे का पता चलता है ।

"समान उत्पाद" से संबद्ध प्रचालन कार्यकलाप	लागत करोड़ रुपए में	प्रचालन लागत का % हिरसा
अनुसंधान डिजाइन एवं विकास व्यय	***	***
जांच एवं संयोजन सहित विनिर्माण व्यय	***	***
कुल	***	***

25. निम्नलिखित तालिका में तेजस तथा आयातकों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों की तुलना की गई है । जैसा कि स्पष्ट होता है पृथ्वी, वीएमपीएल द्वारा भारत में केवल संयोजन संबंधी प्रचालन किए जाते हैं । वॉवी द्वारा भारत से बाहर अपने अधिकांश प्रचालन किए जाते हैं ।

कार्यकलाप	तेजस	पृथ्वी	वीएमपीएल	हुआवेई
भारत में आई पी आर निवासी के साथ भारत में अनुसंधान	हां	नहीं	नहीं	नहीं
भारत में डिजाइन एवं विकास	हां	नहीं	नहीं	नहीं
भारत एवं अन्य देशों में ई एम एस संविदागत विनिर्माण	हां	नहीं	नहीं	नहीं
भारत में संयोजन एवं जांच प्रक्रिया "विनिर्देशन विकास"	हां	नहीं	नहीं	नहीं
भारत में अंतिम संयोजन एवं जांच	हां	हां	हां	नहीं
भारत में निष्पादित बिक्री पश्चात "बग फिक्स/संवर्धन/उन्नयन"	हां	नहीं	नहीं	नहीं
भारत में बिक्री पश्चात-पुर्जों की आपूर्ति/प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता	हां	नहीं	नहीं	हां

विरोधी हितबद्ध पार्टियों के अनुरोध

26. हुआवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि आवेदक संबद्ध वस्तु का स्वयं आयातक है और उसके पास वर्तमान याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि आवेदक विशिष्टीकृत उत्पादकों अर्थात् ई एम एस से संघटकों के पर्याप्त पुर्जे प्राप्त करता है। आधार के बारे में सी सी एम ई ने भी यही आपत्ति उठाई है।

27. वावी ने आगे यह अनुरोध किया है कि आयातक द्वारा सेलेस्टिका, जो एक ई एम एस है, से संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है जो चीन जन.गण. में अनेक कार्यालयों के जरिए प्रचालन करती है। चूंकि आवेदक ने संबद्ध देशों से वस्तु का स्वयं आयात किया है, इसलिए वह इस मामले में "घरेलू उद्योग" का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

28. हुआवी ने यह भी अनुरोध किया है कि "घरेलू उद्योग" की पात्रता हेतु आवेदक का दावा आर एंड डी के मापदंड पर आधारित है जो दोषपूर्ण है क्योंकि आर एंड डी इस संबंध में प्रयोग में लाया जाने वाला एकमात्र कारक नहीं है।

29. डब्ल्यू टी ओ पैनल रिपोर्ट डब्ल्यू टी/डीएस/337/आर के पैरा 7.112, 7.114 तथा 7.124 का हवाला दिया गया है। इन पैराओं में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 की व्याख्या दी गई है। इसके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्पादों की समस्त श्रेणियों और समूहों को घरेलू उद्योग का भाग माना जाएगा।

30. हुआवी ने यह भी दावा किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) ने भी आवेदक को आयातक के रूप में वर्गीकृत किया है।

31. यह याचिका कुछ उत्पादों एस टी एम 256, एस टी एम 64 एवं डिजीटल क्रॉस कनेक्टों से संबंधित है। ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका आवेदक न तो विनिर्माण करता है और न ही उनकी बिक्री करता है। इसलिए भी उनके पास कोई आधार नहीं है।

32. सी सी सी एम ई ने जांच अवधि के दौरान आवेदक द्वारा भारतीय उत्पादन में 84.7% हिस्सा होने के बारे में किए गए दावे का खंडन किया है और आवेदक आधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

33. इस दावे के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। मै. मेजरमेंट एंड कंट्रोल्स लिमिटेड इनकी याचिका का समर्थन करता है।

34. "अप्रकटित एसोसिएशन के पत्र" में एम सी आई, बी ई एल तथा आई टी आई को गलत ढंग से भारतीय उत्पादकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एम सी आई ने आज की तारीख तक संबद्ध वस्तु की एक भी इकाई की बिक्री नहीं की है। बी ई एल तथा आई टी आई द्वारा एच एफ सी एल एवं पृथ्वी लिमिटेड की तर्ज पर कार्य किया जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

35. याचिकाकर्ताओं ने सी एम ए आई (एसोसिएशन) का एक पत्र दायर किया है जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनाता है।

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विरोधी पार्टियों द्वारा नार्वे से फ्रेंड सालोमन से संबंधित मामले में पैनल की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है। तथा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग हैं। उक्त मामले में ई सी ने यह जांच नहीं की थी कि क्या उन उत्पादकों, जिन्हें संबद्ध उत्पाद का उत्पादक नहीं माना गया है, द्वारा कोई कार्यकलाप किया गया है या नहीं। जिसे ऐसा कार्यकलाप माना जाएगा जो उत्पादन का भाग बन सकता है।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विरोधी पार्टियों द्वारा नार्वे से फ्रेंड सालोमन से संबंधित मामले में पैनल की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है तथा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा अनुच्छेद 4.1 की दी गई व्याख्या का दायरा सीमित है क्योंकि वह अनुच्छेद की साधारण भाषा पर ही आधारित थी। इस संबंध में रिपोर्ट का पैरा 7.115 प्रासंगिक है:

7.115 इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि फ्लेटिड सालोमन इस मामले में ई सी द्वारा अभिज्ञात समान उत्पाद के दायरे में आता है। इस प्रकार अनुच्छेद 4.1 की साधारण भाषा की हमारी व्याख्या के आधार पर हम यह मानते हैं कि ऐसे किसी उद्यम को समान उत्पाद का "उत्पादक" और इस प्रकार घरेलू उद्योग का भाग माना जाना

चाहिए जिसने कम से कम पहली बार समान उत्पाद या उसके किसी रूप का उत्पादन किया है।

पद टिप्पणी 289 में निम्नानुसार उल्लेख है:

289. ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें ऐसा कोई उद्यम जिसका उत्पाद समान उत्पाद के दायरे में आता है, इतने कम स्तर पर कार्यकलाप में संलग्न पाया जा सकता है ताकि इस निष्कर्ष को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सके कि वह वस्तुतः समान उत्पाद का "उत्पादन" नहीं करता है तथापि, जांच के दौरान घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय केवल फ्लोटिंग कार्यकलाप की मात्रा पर विचार नहीं किया गया था। अतः हमारे समक्ष इस मामले के तथ्यों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं है। (जोड़ दिया गया)

38. अतः पैनल ने पाद टिप्पणी 289 में यथाउल्लिखित कुछ परिस्थितियों को अनुच्छेद 4.1 की अपनी व्याख्या से अलग रखा है। अतः पैनल के निर्णय में ऐसी स्थिति शामिल नहीं है जिसमें ऐसे किसी उद्यम, जिसका उत्पाद समान उत्पाद के दायरे में आता है, ऐसे कार्यकलाप में शामिल है जो या तो काफी अधिक नहीं है या अत्यंत नगण्य है, के संबंध में "घरेलू उद्योग" के भाग के रूप में उसके आधार के निर्धारण हेतु विचार किया जा सकता है।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह याचिका तेजस नेटवर्क्स लि. द्वारा दायर की गई है और इसका समर्थन मेजरमेंट्स एंड कंट्रोल्ल्स लि. ने किया है। पृथ्वी, वी एम पी एल तथा हुबाई ने यह दावा किया है कि इन कंपनियों को "घरेलू उद्योग" माना जाए। इन कंपनियों द्वारा प्रदत्त सूचना की सावधानीपूर्वक जांच विधिक उपबंधों के मद्देनजर की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में दो मुद्दे हैं (क) क्या कंपनी पर उत्पादक के रूप में विचार किया जा सकता है, और (ख) क्या कंपनी पर "पात्र" घरेलू उत्पादक के रूप में विचार किया जाना चाहिए। नियम 2 (ख) में इस संबंध में निम्नानुसार उपबंध है :

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा:

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे कुछेक उदाहरण हैं जब किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जा सकता। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि किसी कंपनी को तभी उत्पादक के रूप में माना जा सकता है जब उसने इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन कार्यकलाप किए हों कि निविष्टि का "पर्याप्त रूपांतरण" बंद हो गया हो। याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए "उत्पादक" के रूप में इन कंपनियों के दावे का खंडन किया है कि ये कंपनियां उत्पादन के इतने अधिक कार्यकलाप नहीं कर रही हैं जिन्हें "पर्याप्त रूपांतरण" आधार पर

घरेलू उत्पादक माना जा सके। तथापि, भारतीय उत्पादक के रूप में इन कंपनियों के दावे का खंडन किए बिना प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन कंपनियों ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए अपेक्षित संबद्ध सी के डी, एस के डी अथवा पुर्जों/संघटकों का आयात कर संयोजन प्रचालनों में संलग्न हैं। चूंकि इस मामले में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सी के डी/एस के डी तथा संघटक शामिल हैं। जहां तक इनका उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादनों में होता है, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि ये कंपनियां विचाराधीन उत्पाद की बड़ी आयातक हैं। चूंकि इन कंपनियों द्वारा सी के डी, एस के डी या संघटक रूप में स्वयं विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त आयात किया जा रहा है, इसलिए इन कंपनियों को किसी भी हालत में "घरेलू उद्योग" के दायरे से अलग रखना जरूरी है।

41. वी एम सी एल तथा पृथ्वी की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि दोनों कंपनियां एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। संबद्ध पार्टी के सौदों के बारे में अपने प्रकटनों में पृथ्वी की वार्षिक रिपोर्ट में वी एम सी एल को संबद्ध पार्टी सूचित किया गया है।

42. वी एम सी एल ने विचाराधीन उत्पाद के न तो घरेलू उत्पादक और न ही आयातक के रूप में निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। तथापि कंपनी द्वारा दिए गए विवरण तर्कों/किए गए अनुरोधों से यह पाया गया है कि कंपनी के प्रचालन पृथ्वी से अत्यधिक निर्यात करते हैं। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि वी एम सी एल ने प्राधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग नहीं किया है यद्यपि उनकी संबद्ध कंपनी ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने यह सिद्ध करने के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की है कि यह घरेलू उत्पादक के रूप में माने जाने के पात्र हैं।

43. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के परिसरों में विस्तृत जांच की। यह देखा गया था कि याचिकाकर्ता ने जनशक्ति तथा संयंत्र एवं उपकरणों में पर्याप्त निवेश किया है और उसके पास अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन, संयोजन, जांच एवं बिक्री पश्चात सहायता से संबंधित समस्त अपेक्षित क्षमताएं हैं। याचिकाकर्ता को उनके द्वारा किए गए आयातों के संबंध में सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया गया था चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को समस्त पुर्जों/संघटकों के बारे में सूचना देने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि-

- i. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से समूची संदर्भ अवधि के दौरान किसी एस डी एच उपकरण का आयात नहीं किया है;
- ii. याचिकाकर्ता ने एस डी एच उपकरण के उत्पादन हेतु कुछेक पुर्जों/संघटकों का आयात किया है। ये पुर्जों/संघटक चीन तथा तीसरे देशों से प्राप्त नहीं किए गए हैं। इजराइल से कोई आयात नहीं हुआ है।
- iii. चूंकि पूर्ण एस डी एच उपकरण का कोई आयात नहीं हुआ है इसलिए उस सीमा तक नियम 2(ख) लागू नहीं होता है और याचिकाकर्ता को संबद्ध वस्तु का आयातक नहीं माना जा सकता। तथापि, चूंकि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र एस डी एच के प्रयोग के लिए निर्दिष्ट पुर्जों/संघटकों पर लागू होता है, इसलिए

याचिकाकर्ता द्वारा पुर्जों/संघटकों का किया गया आयात संगत बन जाता है। तीसरे देशों अर्थात् चीन/इजराइल से भिन्न देशों से हुए पुर्जों/संघटकों के आयात पूर्णतः असंगत हैं और ये नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित आयातों के दायरे में नहीं आते हैं। सत्यापित सूचना से यह पता चलता है कि संघटकों के संबंध में याचिकाकर्ता ने दोहरे उपयोग के संघटकों/पुर्जों और उन संघटकों/पुर्जों का आयात किया है जिनका अनन्य उपयोग एस डी एच उपकरण में हुआ है। यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा संघटकों के आयात के संबंध में चीन से हुए कुल आयातों का हिस्सा कुल उत्पादन लागत का 4.79% बनता है जिनमें से केवल 0.53% ऐसे संघटक/पुर्जे हैं जिनका एस डी एच उपकरण में अनन्य उपयोग हुआ है जबकि अन्य सभी संघटकों/पुर्जों का दोहरा उपयोग हुआ है और ये प्रस्तावित उपाय के दायरे में नहीं आते हैं।

44. आयातों के आरोप को छोड़कर हितबद्ध पार्टियों द्वारा पात्र घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता को अलग रखने को न्यायोचित ठहराते हुए कोई अन्य कारण/आधार नहीं दिया गया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि कंपनी का प्रमुख कार्यकलाप भारत में विनिर्माण करना है जिसमें उत्पादन कार्यकलाप आवश्यक अनुसंधान एवं डिजाइन तथा विकास शामिल है। याचिकाकर्ता ने अपनी उत्पादन कार्यकलाप कम नहीं किया है और उसने व्यापार की शुरुआत नहीं की है। हितबद्ध पार्टियों ने ऐसा कोई न्यायोचित कारण नहीं दिया है जिसकी वजह से याचिकाकर्ता को अलग रखना अपेक्षित हो और इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता को पात्र घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखना उचित नहीं होगा।

45. उपर्युक्त के मद्देनजर नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ वी एम पी एल, पृथ्वी तथा हुआवी पर पात्र घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने में असमर्थ हैं।

46. प्राधिकारी के रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि :

- क. याचिकाकर्ता का उत्पादन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ उत्पादन है;
- ख. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया आयात इतना अधिक नहीं है ताकि याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के क्षेत्र के अयोग्य हो सके।
- ग. पृथ्वी, वी एम पी एल तथा हुआवी जैसे अन्य घरेलू आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए आयात इतने अधिक हैं जिससे कि वे नियम 2(ख) के अंतर्गत अपात्र घरेलू उत्पादक बन जाते हैं।
- घ. याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

47. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि याचिका में आधार की पूर्ति होती है और याचिकाकर्ता नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

अन्य अनुरोध तथा उठाए गए मुद्दे

48. अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित अन्य मुद्दे हैं :-

- क. आवेदक ने न तो अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई है और न ही उसे निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया है । आयातों का ब्यौरा उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है, आयातों के स्रोत तथा उसकी अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है ।
- ख. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आयात के आंकड़े प्राप्त की गई बिक्री या संविदा पर आधारित है । याचिका के प्रपत्र IV क में भारत को की गई बिक्री तथा निर्यात बिक्री का विभाजन नहीं दर्शाया गया है ।
- ग. संबद्ध वस्तु से इतर वस्तु की बिक्री का ब्यौरा इकाई (नग) के रूप में नहीं दिया गया है ।
- घ. याचिकाकर्ता की खुद की वार्षिक रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार आवेदक के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और इस प्रकार संबद्ध वस्तु के आयातों का आवेदक के निष्पादन पर परिणामी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है ।
- ङ. पी सी एन वर्गीकरण में संबद्ध उत्पाद की विशेषताएं प्रदर्शित नहीं होती हैं ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के बारे में विभिन्न पार्टियों ने अनेक आरोप लगाए हैं । जहां तक निर्धारित प्रपत्र में आयातों, स्रोत एवं अवधि का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आयातों के स्रोत संबंधी दस्तावेज के साथ भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों की सौदेवार सूचना प्रदान की है । प्रपत्र IV-क में निर्यात बिक्री को सूचीबद्ध भी किया गया है । याचिकाकर्ता के लिए IV-क में संबद्ध उत्पाद की केवल बिक्री का ब्यौरा देना अपेक्षित होता है न कि अन्य उत्पादों का । पी सी एन प्रणाली के बारे में हितबद्ध पार्टियों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि कैसे और क्यों पी सी एन प्रणाली त्रुटिपूर्ण है और उत्पाद को परिभाषित करने के लिए विभिन्न मापदंड क्या होने चाहिए । साथ ही साथ हितबद्ध पार्टियों ने दायर किए गए उत्तर में पी सी एन वार सूचना प्रदान की है ।

गोपनीयता

घरेलू उद्योग के अनुरोध

50. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध करते हुए विभिन्न प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यातित पी सी एन के बारे में किए गए गोपनीयता के दावे पर टिप्पणियां की हैं :

- (i) भारत को निर्यातित पी सी एन या उत्पाद का प्रकार भारतीय बाजार में बेचे गए उत्पाद से ही संबंधित है। भारत को निर्यातित उत्पाद के प्रकार को व्यापार से संबंधित संवेदन सूचना मानना कल्पनासीत है।
- (ii) याचिका में किए गए उल्लेख के अनुसार उपभोक्ता विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से पेशकश की विशिष्ट मांग करते हैं। अतः विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट जरूरत की सुस्पष्ट जानकारी है। इस हद तक बाजार में विभिन्न प्रतिस्पर्धी विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्यातित उत्पाद की जानकारी रखते हैं।
- (iii) यदि वह मान भी लिया जाए कि किसी खास ग्राहक को बेचे गए उत्पाद के विशिष्ट प्रकार से संबंधित सूचना संवेदनशील हो सकती है तो उत्पाद का विवरण किसी भी हालत में व्यापार संवेदनशील नहीं हो सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को संबंधित ग्राहक के नाम के बारे में गोपनीयता प्रदान की जा सकती है।
- (iv) पी सी एन प्रकार के बारे में सूचना रोक कर हितबद्ध पार्टियों ने जांच की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का कारगर प्रयास किया है। पी सी एन प्रणाली का उद्देश्य (क) सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत; (ख) आयातों के पहुंच मूल्य एवं घरेलू उद्योग की कीमत कीमत; और (ग) आयातों की पहुंच कीमत तथा घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत के बीच उचित तुलना करना है। जब तक विभिन्न पार्टियों द्वारा आपूर्त पी सी एन की जानकारी पार्टियों को नहीं होती है तब तक घरेलू उद्योग विदेशी उत्पादकों द्वारा निर्यातित उत्पाद के प्रकारों के बारे में जाने बिना क्षति संबंधी अनुरोध नहीं कर सकता है।
- (v) उन्होंने आगे नियम 7 की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें यह उपबंध है कि यदि प्राधिकारी हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे से संतुष्ट नहीं है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना को अस्वीकृत कर देंगे। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया है कि ऐसी किसी स्थिति, जिसमें हितबद्ध पार्टियां अत्यधिक गोपनीयता का दावा करती हैं, वहां घरेलू उद्योग जांच में भाग लेने और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर का जवाब देने से वंचित हो जाता है।

प्रतिवादी निर्यातकों के अनुरोध

ई सी आई टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, इजराइल तथा एच ई टी सी, चीन जन. गण.

51. उन्होंने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :

- (i) पी सी एन के प्रकटन के मुद्दे पर हम यह अनुरोध करना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त पुर्जों/संयोजनों के साथ अगोपनीय याचिका में प्रस्तुत पी सी एन संरचना से संबंधित यह सूचना याचिकाकर्ता की सूची में शामिल नहीं है जिसे 17 जुलाई, 2009 के हमारे पत्र के तहत निर्यातक द्वारा दायर अगोपनीय याचिका में पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है।
- (ii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पी सी एन संरचना में समस्त पुर्जों/संघटकों के आंकड़ें शामिल हैं जिनका निर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पी सी एन संरचना एवं माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुरोध के अनुसार जांच अवधि के दौरान किया गया है।

- (iii) यह सूचना याचिकाकर्ता के प्रकटन मानक के अनुरूप है। परिणामतः यह अनुरोध है कि निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गुणवत्ता और उसके स्वरूप से अगोपनीय याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के मानक और पारदर्शिता की पूर्ति होती है।
- (iv) यह एक सुस्थापित तथ्य है कि कोई अंतिम प्रयोक्ता उत्पाद का ऑर्डर पी सी एन ऑर्डरों के आधार पर नहीं देता है और उन्हें प्रणाली की उपयुक्तता और उसकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करता है। समूची पी सी एन प्रक्रिया इस पाटनरोधी जांच में सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा ऑर्डर दिए गए उपयुक्ता के आधार पर पी सी एन के ब्यौरों में वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा कीमत निर्धारण में हमारे ग्राहक की स्थिति से समझौता स्पष्ट होगा। वस्तुतः याचिकाकर्ताओं को भारत में संबद्ध देशों द्वारा निर्यातित पुर्जों/संघटकों की भली-भांति जानकारी है, जैसा कि आईबीआईएस से पता चलता है और जिस पर याचिका में भरोसा किया गया है। किसी भी स्थिति में निर्यातक पी सी एन/उत्पाद प्रकार का निर्यात नहीं करते हैं। निर्यातक निजी टेलीकॉम कंपनियों के अनुरोध पर ही केवल पुर्जों/संघटकों/संयोजनों का निर्यात करते हैं न कि याचिकाकर्ता के आरोप के अनुसार पी सी एन/उत्पाद प्रकार का। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना से जांच अवधि के दौरान निर्यातित प्रकारों/उपकरण के स्वरूपों का खुलासा होगा और इस बाजार में क्रेताओं के विविध स्वरूप को देखते हुए क्रेता को किए गए निर्यात को सह-संबद्ध करना आसान होगा। वस्तुतः इस बात की पुष्टि याचिकाकर्ता के परामर्शदाता के 30 जुलाई, 2009 के पत्र के पैरा 9 ii में हो जाती है।
- (v) ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसे निर्यातकों ने छुपाया हो, जिससे जांच में बाधा पहुंची हो। पी सी एन का परिकलन माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुरोध के आधार पर किया गया है।
- (vi) अनुरोध है कि याचिकाकर्ता इस स्तर पर माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। निर्यातकों ने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी में अपना विश्वास जताया है जिनके पास पाटन एवं क्षति मार्जिन की गणना का अपेक्षित अनुभव है। यदि उत्पाद के प्रकारों की जानकारी के बिना अनुरोध करने में कोई कठिनाई आ रही है तो इससे सिद्ध करने का सर्वप्रथम दायित्व हितबद्ध पार्टियों के समक्ष सूचना को प्रकट करने का होता है और वह भी जांच की शुरुआत के समय। याचिकाकर्ता इस सूचना को हितबद्ध पार्टियों को उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं और यह भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में उपबंधित हितबद्ध पार्टियों के गोपनीयता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

52. प्राधिकारी ने परिशिष्ट 8 में किए गए उल्लेख के अनुसार उत्पादन लागत हेतु निर्यातक द्वारा प्रदत्त बी ओ एम के ब्यौरों पर भरोसा किया है। इसे दिनांक 24.8.2009 के ई-मेल के जरिए सॉफ्ट कॉपी में दोनों कंपनियों के संबंध में अलग से उपलब्ध कराया गया है और इसे रिकॉर्ड में लिया गया है।

मै. हुआवी टेक्नोलॉजीज कं., लि. चीन जन.गण.

53. उन्होंने गोपनीयता के मुद्दे पर कोई लिखित टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है परंतु उन्होंने पी सी एन ब्यूरो का खुलासा करते हुए उत्तर का अगोपनीय रूपांतरण संशोधित रूप में उपलब्ध कराया है। तथापि, वे अपेक्षानुसार बी ओ एम के ब्यूरो प्रदान करने में विफल रहे हैं।

मै. एल्काटेल-लुसेंट शंघाई बैल कंपनी लि., चीन जन.गण.

54. उन्होंने पी सी एन के ब्यूरो का खुलासा किया है और इस संबंध में इसकी सॉफ्ट एवं हार्ड कापी उपलब्ध कराई है। इसे सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। उन्होंने बी ओ एम के ब्यूरो भी प्रदान किए गए हैं जिन्हें रिकॉर्ड में रखा गया है।

मै. जैड टी ई कार्पो., चीन जन.गण.

55. उन्होंने निम्नानुसार उल्लेख करते हुए इस मुद्दे पर प्राधिकारी को उत्तर दिया है :

- (i) जहां तक कंपनी का संबंध है, जांच अवधि के दौरान एक समान पी सी एम या उत्पाद प्रकार के उसके उत्पादों का भारत को निर्यात घरेलू या विदेश स्थित अन्य ग्राहकों को किया गया है। यद्यपि, एस डी एच उत्पादों की ज्ञात विशेषताओं के कारण एस डी एच के ऐसे अनेक उत्पाद खासकर संघटकों के रूप में असाधारण रूप से भारत को निर्यातित प्रकारों के समान हो सकते हैं। इसके अलावा, अलग-अलग ग्राहकों को अलग-अलग बाजारों में बेचे गए अलग-अलग उत्पाद अलग-अलग बाजार की स्थिति और कंपनी की कार्यनीति के अनुरूप होने चाहिए। पूर्वोक्त के आधार पर पी सी एन या भारत को निर्यातित इसके प्रकारों का निर्यातकों के समक्ष एक बार प्रकटन हो जाने के बाद याचिकाकर्ता आसानी से कंपनी की बाजारी स्थिति से संबंधित कार्यनीति को पहचान सकते हैं और वे भारत को निर्यातित पी सी एन या इसके प्रकारों की कीमत लागत का अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसा कि याचिका ("याचिका") में प्रदर्शित किया गया है जो कल्पनातीत ढंग से समस्त संवेदनशील व्यापारिक सूचना है, जिसका भारतीय बाजार में एच डी एच उत्पादों की उचित प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (ii) यद्यपि, कंपनी को प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट जरूरत की सुस्पष्ट जानकारी है, तथापि, अपने आपूर्तिकर्ता के साथ ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट संविदा में पकार, विवरण एवं कीमत परामर्श जैसी समस्त व्यापारिक सूचना संविदा की गोपनीयता के रूप में निर्धारित संवेदनशील व्यापार सूचना होनी चाहिए। इसकी वजह से संविदा की पार्टियों को छोड़कर बाजार में कोई अन्य प्रतिस्पर्धी विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्यातित उत्पाद की जानकारी नहीं रखता है। सूचना के प्रकार का खुलासा करने का याचिकाकर्ता का अनुरोध इस बात का सशक्त साक्ष्य

है कि उपर्युक्त व्यापार सूचना याचिकाकर्ता के लिए गोपनीय है अर्थात् इसे "विभिन्न प्रतिस्पर्धियों" के समक्ष प्रकटित नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि याचिकाकर्ता ने अपनू अनुरोध में उल्लेख किया है। उपर्युक्त व्यवहार और सिद्धांत के अनुरूप यदि पृष्ठ सं. 46-48, सं. 78-81 और सं. 84-89 पर आयात के ब्यौरों, पाटन मार्जिन की गणना तथा चीन से भारत को निर्यातित पी सी एन एवं एस डी एच उत्पादों के प्रकारों की कीमत कटौती से संबंधित सूचना स्पष्ट नहीं है, तो याचिकाकर्ता चीन के निर्यातकों के विरुद्ध जांच करने हेतु आयात सूचना में कांट-छांट कर सकता है अथवा याचिकाकर्ता के प्रति अवैध रूप से संवेदनशील व्यापार सूचना को प्राप्त करने के बारे में संदेह किया जा सकता है। इस प्रकार, हमारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में उपर्युक्त सूचना के मूल स्रोत और उसे प्राप्त करने के प्राधिकार का खुलासा करने का निर्देश दें। इसके अलावा, चूंकि उसे उपर्युक्त पृष्ठों पर किए गए उल्लेख के अनुसार संवेदनशील व्यापार सूचना की जानकारी है तो हमें इस बात का आश्चर्य है कि याचिकाकर्ता याचिका में दी गई सूचना की अनदेखी क्यों कर रहा है और ऐसी सूचना का पुनः अनुरोध कर रहा है।

- (iii) याचिका में याचिकाकर्ता के अनुसार चीन से हुए निर्यात का उत्पाद विवरण हर प्रकार से संवेदनशील व्यापार सूचना है। प्रत्येक निर्यातक के लिए उत्पाद विनिर्देशन एवं उसकी संरचना विवरण में निहित होती है जिसमें भारत में किसी कंपनी की विपणन नीति एवं बाजारी स्थिति का भी उल्लेख होता है। अतः यदि विवरण का खुलासा किया जाता है तो याचिकाकर्ता जांच के लिए अत्यंत जरूरी अधिक संवेदनशील व्यापार सूचना हासिल कर लेगा। इस बीच यह भी सुविज्ञात तथ्य है कि कंपनी के ग्राहक के रूप में भारतीय नेटवर्क प्रचालक "सूची खरीद" के रूप में एस डी एच उत्पादों की खरीद करते हैं जिससे कंपनी के प्रतिस्पर्धी अपने नेटवर्क की विशिष्ट विशेषताएं हासिल करने से वंचित हो सकते हैं। यदि पी सी एन सार्वजनिक हो जाती है तो भारतीय प्रचालकों की नेटवर्क विशेषताएं वास्तविक गोपनीयता के रूप में प्रकटित हो जाएंगी, जो कंपनी के लिए अस्वीकार्य होगा और उपर्युक्त प्रचालक भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे।
- (iv) हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि याचिका के पृष्ठ सं. 76 पर याचिकाकर्ता ने पाटन मार्जिन एवं सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत की गणना की है और याचिका के पृष्ठ सं. 84-89 पर याचिकाकर्ता ने कीमत कटौती एवं पहुंच कीमत, आयात कीमत एवं मूल्य की गणना की है जबकि याचिकाकर्ता ने पी सी एन, उत्पाद के प्रकार एवं विवरण के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। जांच करने में संवर्ती भागीदारी हेतु हमारा अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इसके साथ, याचिकाकर्ता को अपने उत्पादों के विवरण के साथ पी सी एन या उसके प्रकारों का प्रकटन करने का निर्देश दें, ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता जांच की कार्यवाही में बाधा डालेगा।
- (v) पूर्वोक्त के अतिरिक्त हमारा यह विश्वास है कि यह कंपनी नियमों का अनुपालन करती आ रही है और उसने जांच में बाधा नहीं डाली है। गोपनीयता के लिए कंपनी सहित चीन के निर्यातकों के हित की रक्षा हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध

है कि वह जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यातित पी सी एन एवं उसके प्रकार तथा एस डी एच उत्पादों के निर्यात का खुलासा करने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध से इंकार कर दें।

56. मै. जैड टी ई कार्पोरेशन ने 26 अगस्त, 2009 के ई-मेल द्वारा यह सूचित किया था कि उनके उत्तर के अनुसार निर्यात की मात्रा डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों की तुलना में कम बताई गई प्रतीत होती है। इसके उत्तर में कंपनी के प्रतिनिधि ने यह उल्लेख किया कि निर्यात सूचना तैयार करते समय कंपनी ने केवल निर्यात पर ही विचार किया था, जिनके संबंध में जांच अवधि में आने वाली निकासी तारीख के साथ उक्त अवधि के दौरान राजस्व की कसौली की गई है। इसी सिद्धांत के अनुसार जांच अवधि के दौरान निकासी की तारीख के साथ निर्यात एवं उसके राजस्व को जांच अवधि में स्वीकार नहीं किया गया है, जिसकी वजह यह रही है कि वास्तविक कीमत, लागत और इसी प्रकार की चीजों को कंपनी ने हिसाब में नहीं लिया है। आगे यह दलील दी गई है कि कंपनी की लेखा प्रणाली के अनुसरण में सामान्यतः संविदा के अंतर्गत सम्पन्न राजस्व को तब स्वीकार किया जाएगा जब संविदा के सभी उत्पादों का पूर्णतः निर्यात हो जाएगा, जो इस उद्योग में प्रचलित सुविधित एवं सामान्य प्रंपरा है। उनके दावे के अनुसार यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर जांच प्राधिकारी द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

57. आगे यह अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त कारण से ऐसा हो सकता है कि कुल संविदा के भाग के कुछ निर्यातों की गणना प्रश्नावली के उत्तर में न की गई हो तथापि, यह कंपनी यह सूचना तैयार कर रही है जिसे शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

मै. फाइबर होम टेलेकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि., चीन जन. गण.

58. विचाराधीन उत्पाद के लिए पी सी एन की गोपनीयता और सम्पन्न उत्पाद के बारे में फाइबर होम निम्नलिखित विचारों की सलाह देगा :

- i. किसी एस डी एच उत्पाद का कार्य उसमें प्रयुक्त प्रमुख संघटकों और विशिष्ट डिजाइन के रूप में होता है जिसके तहत उसका उत्पादन और उसका संयोजन किया जाता है जिससे वह उत्पाद एक-दूसरे से अलग हो जाता है और उसकी दूसरे उत्पादों की तुलना में अलग पहचान बनती है तथा पी सी एन के अलग-अलग कोड इस उद्योग में व्यापार प्रौद्योगिकी की प्रमुखता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित पी सी एन प्रणाली में 15 कोड शामिल हैं, जिनमें 15 तकनीकी विशेषताओं का उल्लेख है और जिसमें यह उल्लेख होगा कि किस प्रकार निर्यातक उत्पादकता के पास अपने उत्पादों के अलग-अलग प्रकार हैं। अतः कंपनी की व्यापार क्षमता के रूप में प्रकटित पी सी एन कोड के नियम को अभिज्ञात करने की क्षमता है जिसका मौखिक संपदा अधिकारों के नियम द्वारा व्यापक संरक्षण किया जाता है।
- ii. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने जांच अवधि के दौरान चीन से निर्यातित पी सी एन के बारे में सूचना प्राप्त की है और यदि निर्यातक याचिकाकर्ता के समक्ष

- अपने समस्त पी सी एन का खुलासा करता है तो पश्चातवर्ती व्यक्ति निर्यात कीमत जैसे प्रमुख आंकड़ों के रूप में पी सी एन के दोनों सैटों की तुलना कर सकेगा जो कि निर्यातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ।
- iii. याचिकाकर्ता के अगोपनीय रूपांतरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उनके पास अपनी आसूचना के जरिए समस्त आयातों की सूचना है और यह याचिका में उल्लिखित निर्यात मात्रा एवं निर्यात कीमत निकालने का आधार है । उपर्युक्त के मद्देनजर हमारा अनुरोध है कि यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह दावा किया है कि उनके पास निर्यात विनिर्देशनों और बाद में निर्यातकों द्वारा आपूर्त पी सी एन के निर्यातों के बारे में समस्त अपेक्षित सूचना (और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत के समय विधिवत स्वीकृत) सूचना है, तो घरेलू उद्योग के लिए यह कोई औचित्य नहीं रहता है कि वे यह सूचना खासकर उस स्थिति में निर्यातकों से मांगें जब उन्होंने उनके द्वारा उत्पादित और बेचे गए समस्त पी सी एन के बारे में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया हो ।
- iv. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अने खुद के उत्पादों के लिए पी सी एन उपलब्ध नहीं कराया है और इसे उपलब्ध कराने के लिए केवल निर्यातकों से अनुरोध करना समझ से परे है और याचिकाकर्ता से प्रकटन करने की मांग करना अनुचित और अतर्कसंगत है । आगे यह अनुरोध किया गया है कि एस डी एच पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए वर्तमान याचिका घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई है और सर्वप्रथम उन्हें निर्यातकों के अनुरोधों पर आरोप लगाने से पूर्व नियम 7 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को सिद्ध करें और उनका अनुपालन करें । हम पाटनरोधी जांच की शुरुआत हेतु याचिका के अगोपनीय रूपांतरण में घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के अत्यधिक उपयोग से संबंधित विस्तृत अनुरोध करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

59. प्राधिकारी ने पी सी एन के ब्यौरों के प्रकटन के बारे में किए गए अनुरोधों और चीन एवं इजराइली कंपनी, जैड टी ई तथा फाइबर होम के संबंध में, ई सी आई द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों को नोट किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्तर देने वाले कम से कम दो प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों अर्थात् हुबाई एवं एल्काटेल ने एन सी वी में पी सी एन के ब्यौरों का खुलासा किया है । अतः अन्य प्रतिवादी निर्यातकों के लिए पी सी एन के ब्यौरों के प्रकटन के संबंध में गोपनीयता का दावा करने का कोई कारण नहीं है जिसमें व्यापार सूचना संवेदनशील होने का दावा किया जाए । अतः प्राधिकारी इन प्रतिवादी निर्यातकों को निर्देश देते हैं कि वे अगोपनीय रूपांतरण में पी सी एन के ब्यौरों का प्रकटन करें ताकि उन्हें सार्वजनिक फाइल में रखा जा सके । प्राधिकारी यह मानते हैं कि यदि यह प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक गोपनीय रूपांतरण में उपर्युक्तानुसार पी सी एन का प्रकटन उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो प्राधिकारी अंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन्हें असहयोगी मानेंगे ।

60. जैड टी ई कार्पोरेशन द्वारा भारत को निर्यातकों के बारे दायर किए गए अपूर्ण आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन आंकड़ों को भारत में हुए आयात के आंकड़ों के रूप में स्वीकार किया गया है जो घरेलू खपत हेतु प्रवेश बिल के निर्गम पर आधारित है। वर्तमान मामले में निर्यात की अनेक प्रविष्टियां डीजीसीआईएंडएस के मामले में दर्शायी गई हैं जिन्हें प्रतिवादी निर्यातक ने सूचित किया गया है और यह दावा कि कंपनी की लेखा प्रणाली में सामान्यतः संविदा के अंतर्गत समस्त राजस्व को तभी स्वीकार किया जाता है जब संविदा के समस्त उत्पाद का पूर्णतः निर्यात कर दिया जाता है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अनुरूप नहीं है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रतिवादी निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान हुई बिक्री को कम दर्शाया है और इसलिए इन आंकड़ों पर इस स्तर पर निर्धारण हेतु विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः अनंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ मै. जैड टी ई कार्पोरेशन को असहयोगी माना है। क्या कंपनी को नए सिरे से प्रस्तावित आंकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए, इस अवधारणा को बाद में अंतिम निर्धारण हेतु स्वीकार किया जाएगा और इसे उपर्युक्त की प्राप्ति के बाद प्राधिकारी विचारार्थ लेंगे।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे

61. आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, जांच एवं मूल्यांकन करने के बाद किसी देश ने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है। उन्होंने आगे यह दावा किया है कि चीन ने भी शामिल होने संबंधी संधि में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि डब्ल्यू टी ओ सदस्य 11 दिसंबर, 2016 के जरिए एन एम ई पाटनरोधी कार्य पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों में यूरोपीय आयोग तथा अमरीका द्वारा चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। यूरोपीय संघ तथा अमरीका विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। भारत में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 31 मई, 2002 के संशोधन के बाद चीन के खिलाफ शुरू की गई समस्त जांचों में व्यवहारिक रूप से चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। 4 जनवरी, 2003 के संशोधन के बाद भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है।

62. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन के उत्पादक भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं। उन्होंने घरेलू बाजार एवं इजराइल में संदत्त और संदेय कीमत के आधार पर इजराइल में सामान्य मूल्य निर्धारित करने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य पूर्व/यूरोपीय क्षेत्र का एक भाग होने के कारण इजराइल के संबंध में विचाराधीन उत्पाद की औसत बिक्री कीमत एशिया में स्थित देशों से उच्चतर होने की संभावना है और इजराइल में वास्तविक सौदा कीमत के संबंध में किसी सूचना के अभाव में बाजार अनुसंधान रिपोर्टों के आधार पर निर्धारित कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच**चीन जन.गण.****बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच**

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा की गई पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) के अनुसार चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है बशर्ते उपर्युक्त नियमों के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उपर्युक्त अनुमान का खंडन किया गया हो।

64. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन के निर्यातक (निर्यातकों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप पैरा(3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उसके विपरीत सिद्ध करते हैं। चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार विषयक प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मापदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

(क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

(ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

(ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है।

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरुआत संबंधी सूचना के परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के अनेक उत्पादकों तथा निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से संबंधित प्रश्नावली और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है और उन्होंने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन किया है। प्रतिवादी उत्पादकों एवं निर्यातकों के प्रश्नावली

के उत्तर तथा बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी उत्तरों की जांच की गई है। मै. फाइबर होम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कम्प्यूनिकेशन लि., मै. जैड टी ई कार्पो., मै. अल्काटेल-बूसेट शंघाई बेल कंपनी लि. तथा मै. हुआवी टेक्नोलॉजीज कंपनी लि., मै. हेंगझाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लि. के संबंध में उत्तर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं और उनमें इस आशय के किए गए दावों के बीच संबंध स्थापित नहीं होता है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना सही है। प्राधिकारी द्वारा व्यक्त अभिमतों पर टिप्पणियां मांगते हुए इनमें से प्रत्येक प्रतिवादी निर्यातक को अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं। मै. हेंगझाऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, के संबंध में यह नोट किया जाता है कि दिनांक *** के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार हेंगझाऊ ईस्टर्न ईसीआई टेलीकॉम लिमिटेड सीमित दायित्व वाली कंपनी की स्थापना हेंगझाऊ ईस्टर्न टेलीकम्युनिकेशन कंपनी (पार्टी क) और ई सी आई टेलीकॉम लिमिटेड, इजराइल (पार्टी ख) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में की गई थी। संयुक्त उद्यम कंपनी की पंजीकृत पूंजी *** मिलियन अम.डॉ. थी जिसमें से ***% का योगदान पार्टी क और ***% का योगदान पार्टी ख द्वारा किया जाना था। संस्था के इस अंतर्नियम (अनुच्छेद ***) के अवलोकन से यह पता चलता है कि इसे "दिनांक *** की संविदा" का एक भाग माना गया है परंतु इस संविदा की प्रति उत्तर में दायर नहीं की गई है। व्यापार लाइसेंस में पंजीकृत पूंजी *** मिलियन दर्शायी गई है जबकि संस्था के अंतर्नियमों में इसे *** मिलियन अम.डॉ. दर्शाया गया है। इसके अलावा, *** के संस्था के संशोधित अंतर्नियम के अनुसार यह देखा गया है कि पंजीकृत पूंजी *** मिलियन अम.डॉ. थी, जिसमें पार्टी क का हिस्सा *** % था। पूंजी सत्यापन रिपोर्ट जिसे सामान्यतः पंजीकृत पूंजी/प्रदत्त पूंजी में परिवर्तन होने पर संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार तैयार किया जाता है, दायर नहीं की गई है। संस्था के अंतर्नियमों में दिनांक *** को आगे और संशोधन किया गया था जिनके अनुसार कंपनी विदेशी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन गई है। उत्तर में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि पार्टी क की शेयरधारिता के प्रतिफल को पार्टी ख के पक्ष में अंतरित क्यों नहीं किया गया था और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में अपनाई गई प्रतिक्रिया क्या थी। इसके अलावा, दिए गए उत्तर के अनुसार यह देखा जाता है कि हेंगझाऊ ईस्टर्न टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एक उत्पादक कंपनी थी परंतु इस कंपनी का व्यापार लाइसेंस दायर नहीं किया गया था। इन महत्वपूर्ण संबंधकारी संपत्तियों के अभाव में प्राधिकारी के लिए प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ एम ई टी का दर्जा प्रदान करना संभव नहीं हुआ है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन के निर्यातकों के ये उत्तर दोषपूर्ण हैं और इसलिए स्वामित्व एवं नियंत्रण, लागत एवं कीमत तथा कंपनी के व्यापार निर्णयों पर उसके प्रभाव, समय-समय पर स्वामित्व के हस्तांतरण, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, भूमि उपयोग के अधिकारों पर उनके प्रभाव से संबंधित मुद्दों की जांच लंबित रहने तक प्राधिकारी का मत यह है कि चीन जन.गण. के इन पांचों उत्पादकों-निर्यातकों को उनके सामान्य मूल्य के प्रारंभिक निर्धारण हेतु बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता। तथापि, बाजार अर्थव्यवस्था के दावे से संबंधित उनके अनुरोधों की जांच की कार्रवाई और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान विस्तृत जांच की जाएगी। इस संबंध में स्थिति की समीक्षा जांच अवधि के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है यदि सत्यापन के उपरान्त ये कंपनियां एम ई टी मापदंडों को पूरा करती हैं।

सामान्य मूल्यचीन जन.गण.

मै. फाईबर होम टेलीकम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि., एल्काटेल-लूसेंट शंघाई बेल कंपनी लि. तथा मै. हुआवी टेक्नोलॉजीज कं. लि.

66. इन परिस्थितियों में प्राधिकारी चीन की उपर्युक्त कंपनियों पर नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा-8 लागू करने की परिस्थिति में नहीं है और उन्हें नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। इन नियमों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर किया जा सकता है :

- क. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर, अथवा
- ख. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य के आधार पर, अथवा
- ग. ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत
- घ. यदि उपर्युक्त विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में संदत्त या संदेय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

67. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में यह उल्लेख किया था कि आवेदक ने यह सुझाव दिया है कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन और बिक्री अमरीका तथा यूरोप में की जाती है और इन देशों को चीन के लिए प्रतिनिधि देश माना जा सकता है। आवेदक ने इन देशों में उत्पादों के नाम और पते प्रस्तुत किए थे।

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देश की लागत और कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बिक्री या तीसरे देश को की गई निर्यात बिक्री तथा तीसरे देश में ऐसे उत्पादकों की उत्पादन लागत के पूर्ण एवं विस्तृत ब्यौरे तथा उनका सहयोग अपेक्षित है। चूंकि इन बाजारों में प्रचलित कीमत और लागत के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है और चीन की प्रतिवादी कंपनियों ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे उचित देश के बारे में कोई दावा नहीं किया है इसलिए प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस मुद्दे की आगे जांच लंबित रहने पर प्राधिकारी मै. फाईबर होम, मै. अल्काटेल एवं मै. हुआवी चीन जन.गण. तथा मै. हैंगझाऊ ई सी आई टेली कम्यूनिकेशन कंपनी लिमिटेड के संबंध में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का अनंतिम निर्धारण करने की कार्रवाई करते हैं। तदनुसार चीन जन.गण. के समस्त निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पादकों के कारखाना सामान्य मूल्य का अनंतिम परिकलन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। एस डी एच उपकरणों के अलग-अलग प्रकारों के लिए पृथक विभिन्न उपकरणों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत उपलब्ध न होने के कारण सामान्य मूल्य का परिकलन समस्त प्रमुख निविष्टियों की वास्तविक भारित औसत कीमत को हिसाब में लेकर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रमुख संघटकों को

प्राप्त कर रहा है, तथापि परिवर्तन लागत तथा घरेलू उद्योग के विधिवत संतुलित एसजीए व्यय को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया है। विभिन्न प्रकार के एस जी एच उपकरणों के लिए अलग से विभिन्न संघटकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत उपलब्ध न होने के कारण सामान्य मूल्य का परिकलन समस्त प्रमुख निविदियों की वास्तविक भारत औसत कीमत को हिसाब में लेकर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अपने संघटक प्राप्त किए हैं। सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विधिवत संतुलित परिवर्तन लागत तथा घरेलू उद्योग के एस जी ए व्यय को स्वीकार किया गया है। 5 प्रतिशत का उचित लाभ मार्जिन जोड़ने के बाद सामान्य मूल्य निकाला गया है। गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत चीन के उत्पादकों द्वारा निर्यातित पी सी एन का भारत औसत सामान्य मूल्य नीचे दर्शाया गया है।

कंपनी का नाम	पी सी एन की संख्या	मात्रा (नग)	भारत औसत सामान्य मूल्य (अम.डॉ./नग)
मै. फाइबरहोम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि.	***	***	***
एल्केटल-लुसेट शंघाई बेल कं. लि.	***	***	***
मै. हुआवी टेक्नोलॉजीज कं. लि.	***	***	***
मै. हैंगझोऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कं. लि.	***	***	***

इजराइल

मै. ई सी आई टेलीकॉम लि., इजराइल

69. कंपनी ने सामग्री के बिल के साथ विभिन्न परिशिष्टों में सूचना प्रदान की है जिसकी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातित 119 पी सी एन में से केवल 6 नगों की बिक्री घरेलू बाजार में की गई है और 7 की बिक्री तीसरे देशों में की गई है। चूंकि इस प्रकार की समस्त घरेलू बिक्रियां और तीसरे देशों को हुई बिक्रियां लाभ में की गई हैं, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू बाजार/तीसरे देश में की गई बिक्री के आधार पर किया गया है। शेष पी सी एन की बिक्री भारतीय बाजार को छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं की गई है। अतः प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक के अनुसार उत्पादन लागत तथा उचित लाभ मार्जिन को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु हिसाब में लिया गया है। तदनुसार सामान्य मूल्य निम्नानुसार बनता है :

कंपनी का नाम	पी सी एन की संख्या	मात्रा (नग)	भारत औसत सामान्य मूल्य (अम.डॉ./नग)
मै. ई सी आई टेलीकॉम लि., इजराइल	***	***	***

निर्यात कीमत**चीन जन.गण. के प्रतिवादी निर्यातक****मै. एल्केटेल-लुसेंट शंघाई बेल कं. लि., चीन जन.गण.**

70. प्राधिकारी के पास दायर उत्तर के अनुसार उन्होंने जांच अवधि के दौरान *** पी सी एन परिवर्तकों का भारत को निर्यात किया है जिनमें *** नग शामिल हैं। उनके द्वारा दायर संशोधित उत्तर के अनुसार निकासी, अंतरदेशीय एवं समुद्री भाड़े तथा बीमा, बैंक प्रभार, ऋण लागत, पैकिंग लागत एवं वैट के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। वैट समायोजन को छोड़कर समस्त समायोजनों की अनुमति सत्यापन के अधीन प्रदान की गई है। वैट के संबंध में केवल हॉर्डवेयर के लिए 0.04% की दर से दावा किया गया है। तथापि, प्राधिकारी ने पुनः सत्यापन के अधीन हॉर्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के अधीन इस समायोजन की गणना कुल मूल्य के 4% की दर से की है। प्रत्येक पी सी एन के संबंध में कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली गई है और तदनुसार व्यापार के समान स्तर पर सामान्य मूल्य के साथ उसकी तुलना की गई है।

मै. फाइबरहोम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि. चीन जन.गण.

71. प्राधिकारी के पास दायर उत्तर के अनुसार उन्होंने जांच अवधि के दौरान *** पी सी एन परिवर्तकों का भारत को निर्यात किया है जिनमें *** नग शामिल हैं। इनमें से *** कार्ड हैं और इनके संबंध में मात्रा का उल्लेख किया गया है जिन्हें एन ई पी के निर्धारण हेतु शामिल किया गया है। अनंतिम उपाय के लिए प्रत्येक पी सी एन के संबंध में कारखाना स्तर पर निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है जो प्रतिवादी निर्यातक द्वारा समायोजनों आदि के किए गए उक्त दावों की पुष्टि हेतु रिकॉर्डों के सत्यापन के अधीन है।

मै. हुआवी टेक्नोलॉजीज लि. चीन जन.गण.

72. प्राधिकारी के पास प्रस्तुत उत्तर के अनुसार उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को *** पी सी एन परिवर्तकों का निर्यात करने का दावा किया है जिसमें *** नग शामिल हैं। इनमें से *** पी सी एन कार्ड हैं परंतु इन *** पी सी एन के संबंध में किसी मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः एन ई पी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ इन्हें शामिल नहीं किया गया है। दावा किए गए समायोजनों की प्राधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण हेतु अनुमति दी है जो प्राधिकारी के आगे और सत्यापन के अधीन हैं।

मै. हांगझोऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कं. लि. चीन जन.गण.

73. प्राधिकारी के पास प्रस्तुत उत्तर के अनुसार उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को *** पी सी एन परिवर्तकों का निर्यात करने का दावा किया है जिसमें *** नग शामिल हैं। एन ई पी की गणना हेतु दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है और इस प्रकार दावा

की गई एन ई पी की अनुमति प्राधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रदान की है जो सत्यापन के अधीन है ।

इजराइल

मै. ई सी आई टेलीकॉम लि. इजराइल

74. प्राधिकारी के पास प्रस्तुत उत्तर के अनुसार उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को *** पी सी एन परिवर्तकों का निर्यात करने का दावा किया है जिसमें *** नग शामिल हैं । समुद्री भाड़े, विदेशी भाड़े, बीमा, भंडारण, वित्तीय लागत एवं वारंटी के लिए समायोजनों का दावा किया है । सत्यापन के अधीन रहते हुए प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ उनकी दावानुसार अनुमति दी गई है ।

पाटन मार्जिन

75. प्राधिकारी ने एस डी एच उपकरणों के विभिन्न प्रकारों की वास्तविक और ऑप्टिकल विशेषताओं में अंतर को स्वीकार किया है और तदनुसार उन्होंने समनुरूपी विनिर्देशनों की तुलना में आयातित एस डी एच उपकरणों की भौतिक एवं ऑप्टिकल विशेषताओं तथा रूपांतरणों पर विचार करने के बाद निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना की है । प्रत्येक पी सी एन के संबंध में अलग-अलग सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के आधार पर तुलना की गई है और तत्पश्चात भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु भारित औसत एन ई पी के साथ की गई है । इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

कंपनी का नाम	भारित औसत सामान्य मूल्य (अम.डॉ./नग)	भारित औसत निर्यात मूल्य (अम.डॉ./नग)	पाटन मार्जिन (अम.डॉ./नग) (%)
मै. फाइबरहोम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि.	***	***	240% -250%
एल्केटल-लुसेंट शंघाई बेल कं. लि.	***	***	30%-40%
मै. हुआवी टेक्नोलॉजीज कं. लि.	***	***	50%-60%
मै. हैगझोऊ ई सी आई टेलीकम्युनिकेशन कं. लि.	***	***	90%-100%
मै. ई सी आई टेलीकॉम लि., इजराइल ।	***	***	नकारात्मक

क्षति निर्धारण

76. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दपवों के बारे में हितबद्ध पार्टियों के विचारों को नोट किया है और अनंतिम क्षति निर्धारण तथा कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ इस जांच परिणाम में अनिवार्य कारकों की जांच की है ।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सुझाव

77. घरेलू उद्योग ने क्षति के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं.

- (i) ग्राहकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद की जरूरत अपने दूरसंचार नेटवर्क के ऑप्टिकल ट्रांसमिशन आधार की स्थापना के लिए होती है। यह उनके लिए पूंजीगत वस्तु की खरीद होती है। अंतर्ग्रस्त निवेश के भारी मूल्य के कारण ग्राहक खरीद की सुस्थापित प्रणाली का अनुपालन करते हैं।
- (ii) बी एस एन एल, एम टी एन एल तथा रेल टेल जैसी कंपनियां खुली निविदा प्रणाली का पालन करती हैं जबकि निजी प्रतिस्पर्धी (यथा भारती, रिलायंस, टाटा कम्यूनिकेशन आदि) प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर ई पी) प्रक्रिया के जरिए बंद निविदा प्रणाली का अनुपालन करते हैं।
- (iii) खुली निविदाओं में समस्त आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, ऐसी बोलियां समस्त भागीदार आपूर्तिकर्ताओं की मौजूदगी में खोली जाती हैं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उद्धृत कीमतों की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। बंद निविदाओं में ग्राहक भाव दरें आमंत्रित करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और तत्पश्चात सामान्यतः सर्वोत्तम वाणिज्यिक प्रस्ताव (न्यूनतम कीमत, ऋण शर्तें आदि) के आधार पर ऑर्डर प्रदान करते हैं।
- (iv) दोनों प्रणालियों में कीमत सौदेबाजी से इंकार नहीं किया जाता है। कीमत का इस प्रकार का नियतन विनिर्दिष्ट मात्रा या अस्थायी मात्रा के लिए हो सकता है। तथापि, वास्तविक पोत लदान, दर संविदा की अवधि (12-14 माह की) के दौरान किया जाता है।
- (v) शामिल व्यापार की उच्च मात्रा पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता अलग-अलग ग्राहकों की जरूरत का नियमित रूप से पता लगाते हैं और किए गए प्रत्येक प्रस्ताव पर कड़ी निगरानी रखते हैं।
- (vi) याचिकाकर्ता को ग्राहकों द्वारा की गई खरीद की पूर्ण जानकारी होती है। याचिकाकर्ता को ग्राहकों द्वारा लिए गए खरीद के निर्ण की यथोचित जानकारी होती है।
- (vii) याचिकाकर्ता ने नियमित रूप से विकसित इस बाजार आसूचना के आधार पर क्षति अवधि के दौरान प्राप्त किए और गंवाए गए विभिन्न ऑर्डरों के बारे में सूचना समेकित की है।
- (viii) विभिन्न इच्छुक आपूर्तिकर्ता अप्रत्यादेय कीमतें उद्धृत करते हैं। इस प्रस्ताव के बाद यद्यपि कीमत में आगे और कमी आने की संभावना होती है, लेकिन कीमत में वृद्धि होने की संभावना नहीं होती है।
- (ix) घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को विदेशी उत्पादकों एवं भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए प्रस्तावों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए इन प्रस्तावों के आधार पर क्षति मार्जिन का निर्धारण भी किया जाना चाहिए।

आयात मात्रा का निर्धारण

78. प्राधिकारी ने गौण स्रोतों से याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सूचना, आई बी आई एस से याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, प्रतिवादी निर्यातकों एवं आयातकों द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच आयात की मात्रा के निर्धारण हेतु की है। जहां तक जांच अवधि का संबंध है, प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया है। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए चूंकि किसी भी निर्यातक ने निर्धारित मात्रा और ढंग से सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और अलग-अलग अवधियों के लिए सूचना प्रदान की है इसलिए प्राधिकारी याचिका में निहित सूचना को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।

मांग का निर्धारण

79. प्राधिकारी ने देश में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा समस्त स्रोतों से हुए आयातों की राशि के रूप में किया है। इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में देखी जा सकती है :

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08	2005-06 की तुलना में जांच अवधि वार्षिकीकृत
नगों के संबंध में						
चीन	***	***	***	***	***	1364%
इजराइल	***	***	***	***	***	35%
संबद्ध देश	***	***	***	***	***	240%
अन्य देश	***	***	***	***	***	151%
भारत में आयात	***	***	***	***	***	186%
उत्पाद शुल्क रिकॉर्डों के अनुसार घरेलू उद्योग की बिक्री	***	***	***	***	***	175%
घरेलू उद्योग के अनुमान के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	***	***	***	***	***	
मांग	51,308	118,500	81,186	94,027	70,520	183%
मूल्य के रूप में - लाख रुपए						
चीन	***	***	***	***	***	1159%
इजराइल	***	***	***	***	***	183%
संबद्ध देश	***	***	***	***	***	334%
अन्य देश	***	***	***	***	***	229%
भारत में आयात	***	***	***	***	***	270%
घरेलू उद्योग की बिक्री	***	***	***	***	***	234%
अन्य भारतीय उत्पादकों की अनुमानित बिक्री	***	***	***	***	***	
मांग	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062	262%

80. विद्युतशक्ति उत्पाद की मांग में नग एवं मूल्य दोनों रूपों में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित होती है। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि देश में मांग में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद वे संबद्ध देशों से हुए पाटन के कारण इसका लाभ नहीं उठा सके हैं। घरेलू उद्योग के इस आरोप की पुष्टि की गई है और मांग 100 (2005-06) से बढ़कर 183 (जांच अवधि) हो गई है। तथापि, घरेलू उद्योग की तदनुसूची बिक्री इस अवधि के दौरान बढ़कर केवल 175 हुई है।

आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

81. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के नियम के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार उपबंध है: -

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है।"

82. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08
संबद्ध देश	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142
अन्य	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588
कुल आयात	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730
भारतीय उत्पादन	9,930	24,337	10,978	17,053	12,790
भारतीय खपत	51,308	118,500	81,186	94,027	70,520
आयातों का बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	31.49%	47.18%	45.19%	41.32%	41.32%
अन्य	49.15%	32.28%	41.29%	40.54%	40.54%
भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से हुए आयात	162.73 %	229.72 %	334.20 %	229.54%	227.85%

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि, जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों की मात्रा (वार्षिकीकृत) (नगों के रूप में आकलित) मात्रा में आधार वर्ष 2005-06 की तुलना में लगभग 140% की वृद्धि हुई है। क्षति अवधि की तुलना में उत्पाद की कुल भारतीय खपत में संबद्ध देशों का हिस्सा 31% से अत्यधिक बढ़कर 41% हो गया है। मात्रा के संबंध में सबद्ध देशों से समग्र आयात में 2005-06 की तुलना में जांच अवधि के दौरान काफी अधिक लगभग 234% (वार्षिकीकृत) की वृद्धि हुई है।

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08	2005-06 की तुलना में जांच अवधि वार्षिकीकृत
आयातों की संख्या						
चीन	2,502	9,959	10,056	34,132	25,599	1364%
इजराइल	13,657	45,948	26,632	4,724	3,543	35%
संबद्ध देश	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142	240%
अन्य देश	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588	151%
कुल आयात	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730	186%
आयात मूल्य लाख रु. में						
चीन	2,461	6,717	14,564	28,500	21,400	1159%
इजराइल	13,433	30,989	38,570	24,553	18,414	183%
संबद्ध देश	15,894	37,706	53,134	53,085	39,814	334%
अन्य देश	24,805	25,802	48,545	56,791	42,593	229%
कुल आयात	40,699	63,508	101,679	109,876	82,407	270%
भारतीय उत्पादन						
मात्रा	9,930	24,337	10,978	17,053	12,790	170%
मूल्य लाख रुपए में	9,767	16,414	15,898	22,207	16,655	227%
भारतीय उत्पादन की तुलना में भारतीय देशों से आयात						
मात्रा	163%	230%	334%	228%	228%	141%
मूल्य लाख रुपए में	163%	230%	334%	239%	239%	147%

84. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों में समग्र रूप में तथा भारत में उत्पादन की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भारत में खपत की तुलना में आयात

85. भारत में खपत की तुलना में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08	2005-06 की तुलना में जांच अवधि वार्षिकीकृत
आयातों की संख्या						
चीन	2,502	9,959	10,056	34,132	25,599	1364%
इजराइल	13,657	45,948	26,632	4,724	3,543	35%
संबद्ध देश	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142	240%
अन्य देश	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588	151%
कुल आयात	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730	186%
आयात मूल्य लाख रु. में						
चीन	2,461	6,717	14,564	28,500	21,400	1159%

इजराइल	13,433	30,989	38,570	24,553	18,414	183%
संबद्ध देश	15,894	37,706	53,134	53,085	39,814	334%
अन्य देश	24,805	25,802	48,545	56,791	42,593	229%
कुल आयात	40,699	63,508	101,679	109,876	82,407	270%
भारतीय खपत						
मात्रा	51,308	1,18,500	81,186	94,027	70,520	183%
मूल्य लाख रुपए में	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062	262%
भारतीय खपत की तुलना में संबद्ध देशों से आयात						
मात्रा	31.49%	47.18%	45.19%	41.32%	41.32%	131%
मूल्य लाख रुपए में	31.50%	47.23%	45.19%	40.19%	40.19%	128%

86. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात जो वर्ष 2005-06 के दौरान केवल 31.5% थे, वे जांच अवधि में भारत में खपत की तुलना में बढ़कर 41.32% हो गए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पर आयातों का मात्रात्मक प्रभाव प्रतिकूल रहा है।

आयातों का कीमत प्रभाव

87. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा पर्याप्त गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में गिरावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक ग्राहक अपनी विनिर्दिष्ट अपेक्षा की पूर्ति हेतु एस डी एच उपकरण की खरीद करता है। एक स्थान पर किसी ग्राहक द्वारा प्रयुक्त एस डी एच उपकरण संबद्ध भौतिक एवं आटिकल गुणधर्मों के अनुसार दूसरे स्थानों पर प्रयुक्त एस डी एच उपकरण से अलग हो सकते हैं। इसके मद्देनजर कीमत कटौती के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा विक्रीत अत्यधिक समान उत्पाद के प्रकार पर विचार किया है और उसकी तुलना आयातित उत्पाद के प्रकार के साथ की है। जहां कहीं कोई समनुरूपी मॉडल नहीं मिला है, वहां प्राधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए आयातित उत्पाद की तुलना में कम रूपांतरण वाले मॉडल पर विचार किया है ताकि कीमत कटौती को अधिक न दिखाया जा सके। निर्यातित अलग-अलग पी सी एन के लिए कीमत कटौती का निर्धारण करने के बाद प्राधिकारी ने संबद्ध मात्रा पर विचार करने के बाद प्रतिवादी निर्यातक के लिए भारत औसत कीमत कटौती निर्धारित की है। यह देखा गया है कि कीमत कटौती मार्जिन काफी अधिक है।

89. इस संबंध में प्राधिकारी ने प्रत्येक मॉडल (पी सी एन) के लिए अलग से कीमत कटौती की जांच की है। जहां कहीं घरेलू उद्योग ने समनुरूपी मॉडल प्रस्तुत नहीं किया है, वहां प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तुलनीय कम मॉडल पर विचार किया है। यह देखा

गया है कि प्रतिवादी निर्यातकों के लिए आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उसी उपकरण की बिक्री कीमत से काफी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है। वस्तुतः जहां कहीं घरेलू उद्योग ने समनुरूपी मॉडल प्रस्तुत नहीं किया है और तुलना अपेक्षाकृत कम मॉडल के साथ की गई है, वहां यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इन मामलों में बिक्री कीमत में उर्ध्वगामी समायोजन किया जाना चाहिए तथापि, यह देखा गया है कि ऐसे किसी समायोजन के बिना कीमत कटौती का मात्रा अधिक रही है।

90. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि व्यापार जारी रखने के लिए उसे अपनी कीमत को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। परणामतः घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को संबद्ध निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कम एवं पाटित कीमतों के मद्देनजर न्यायोचित स्तर से भी अधिक स्तर तक धीरे-धीरे कम किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि परवर्ती ऑर्डरों में उसी उपकरण की आपूर्ति हेतु विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कीमतें विगत में प्रस्तुत कीमतों से काफी कम रही हैं। दूसरे शब्दों में समान उपकरणों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक परवर्ती कीमत का प्रस्ताव काफी कम कीमत का रहा है। याचिकाकर्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि जहां कहीं याचिकाकर्ता ने समान उपकरण के लिए अपने ग्राहकों को प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में कम कीमत की पेशकश करने की स्वतः परंपरा अपनाई जाती है, वहां विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमत में कमी काफी अधिक और तीव्र होती है। बाजार के लघु आकार को देखते हुए (आपूर्तिकर्ताओं की सीमित और ज्ञात संख्या है) याचिकाकर्ता ने आगे यह दावा किया है कि प्रत्येक आपूर्तिकर्ता एवं उपभोक्ता के कार्यकलापों पर सभी संबंधितों द्वारा नजर रखी जानी चाहिए। अतः विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत कम कीमतों के परिणामस्वरूप न केवल व्यापार में घाटा हुआ है, अपितु उसका घरेलू उद्योग के समस्त परवर्ती प्रस्तावों पर बैच मार्किंग प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार व्यापार में हुए ऐसे घाटे से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को एकमात्र इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए जहां घरेलू उद्योग को बिक्री का नुकसान हुआ है और उसे ऐसे अन्य कारणों से देखा जाना चाहिए जहां घरेलू उद्योग पाटन से बचने के लिए कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ है।

91. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पादों के आयातों से विचाराधीन उत्पाद की कीमत का हास या न्यूनीकरण हुआ है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री लागत एवं बिक्री मात्रा के रुझानों पर विचार किया है। संगत सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

लाख रुपए	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08
बिक्री की लागत	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	144	171	294	294
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि		***	***	***	
बिक्री मात्रा	***	***	***	***	***

सूचीबद्ध	100	139	172	234	234
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि		***	***	***	

92. यह देखा जाता है कि वर्ष 2006-07 में बिक्री लागत में वृद्धि बिक्री राजस्व में हुई वृद्धि से अधिक रही थी। तत्पश्चात् वर्ष 2007-08 में बिक्री लागत में वृद्धि बिक्री राजस्व में हुई वृद्धि से कुछ कम रही थी। तथापि, जांच अवधि में (वार्षिकीकृत) बिक्री राजस्व में वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि से काफी कम रही थी। यद्यपि वर्ष 2007-08 की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री राजस्व में केवल 36% की वृद्धि हुई तथापि इस अवधि में बिक्री लागत में 72% की वृद्धि हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत का हास/न्यूनीकरण हो रहा था।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

93. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है, कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक तथा संभावित गिरावट : घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन के मूल्यांकन से यह पता चलेगा कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इसके अलावा, नीचे की गई विस्तारित चर्चा के अनुसार वर्तमान स्थिति जारी रहने पर घरेलू उद्योग के समक्ष वास्तविक क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

क्षमता एवं क्षमता उपयोग:

94. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस उद्योग में प्रमुख उत्पादन उत्पाद की डिजाइन एवं विकास के रूप में होता है। विनिर्माण की वास्तविक प्रक्रिया और उसका विस्तार जरूरत के अनुसार परिसर के भीतर या उसके बाहर स्थित हो सकती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह संयंत्र एवं मशीनरी में कोई वृद्धि किए बिना समूची भारतीय मांग की पूर्ति कर सकता है। फिर भी इस उद्योग में उत्पादक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा भागीदारों की क्षमताओं का लाभ उठाते हैं जिन्हें बाद में भारत की अगले 10 वर्षों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हासिल हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में क्षमता एवं क्षमता उपयोग को बैद्धिक संपदा तथा आवश्यक डिजाइन एवं विकास कार्य करने एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करने के लिए योग्य कार्मिकों की तैनाती हेतु कंपनी की क्षमता के संदर्भ में देखा जाना

चाहिए। इस कारण याचिकाकर्ता के पास भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि क्षमता एवं क्षमता उपयोग को वर्तमान मामले में असंगत मापदंड माना जाए।

95. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि किसी भी हितबद्ध पार्टी ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि जहां तक उत्पादकों द्वारा वैश्विक रूप से मूल अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास पर उत्तरोत्तर ध्यान केन्द्रित करने का संबंध है, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन अत्यंत खास किस्म का है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उत्पादन करने की क्षमता वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई उचित मापदंड नहीं है क्योंकि विनिर्माता कारकों की संख्या के अनुसार उत्पादन के आंशिक कार्यकलाप बाहर से कराने का निर्णय लेते हैं।

उत्पादन तथा बिक्री मात्रा

96. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्रा में निम्नानुसार घट-बढ़ रही है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08
उत्पादन (नग)	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	203	117	175	175
घरेलू बिक्री (नग)	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	203	117	175	175

97. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री और परिणामी उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह तीन कारकों की नैसर्गिक परिणति रही थी - (क) याचिकाकर्ता ने अपने नए एस टी एम-1, एस टी एम -4, एस टी एम-16 उत्पादों का उत्पादन एवं बिक्री शुरू की जिससे उसके उत्पादों की रेंज बढ़ गई (ख) याचिकाकर्ता ने उच्च प्रौद्योगिकी और समर्थन के कारण अतिरिक्त मात्रा हासिल की है जिसकी भारतीय ग्राहकों ने प्रशंसा की है। (ग) भारत में दूर संचार उपकरणों के बाजार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है- जिसका श्रेय दूरसंचार के क्षेत्र में हुई वृद्धि और दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी क्षमताएं एवं कारोबार योजना तैयार करते समय उसके द्वारा परिकल्पित सीमा से अधिक रहा था और इसमें सहायता प्रदान करने के लिए कंपनी में समय-समय पर अतिरिक्त निवेश किए गए थे। वस्तुतः याचिकाकर्ता ने अधिक उच्च स्तर पर प्रचालन की परिकल्पना की थी जो स्तर अब तक प्राप्त हो सका था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वस्तुतः उसका उत्पादन स्तर अब तक सबसे कम रहा है। कम निष्पादन का कारण चीन/इजराइल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमत में पर्याप्त कमी का रहा है।

98. उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धि तथा याचिकाकर्ता के दावों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में वृद्धि की तुलना मांग में वृद्धि के साथ की गई थी। यह देखा गया था कि यद्यपि घरेलू

उद्योग के उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है तथापि, विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि उत्पादन में हुई वृद्धि से काफी अधिक रही थी। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि आयातों ने बाजार के पर्याप्त अवसरों पर कब्जा कर लिया है जो घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध थे। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन में नुकसान हुआ है और घरेलू उद्योग उस सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने से वंचित हुआ है, जिसे वह पाटन के अभाव में बढ़ा सकता था।

बाजार हिस्सा:

99. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस तथ्य के बावजूद याचिकाकर्ता भारत की सर्वप्रथम ऑप्टिकल नेटवर्किंग उत्पाद कंपनी है, जिसके पास नवीन एवं सृजनकारी पर्याप्त बौद्धिक संपदा है, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि नहीं हुई है। वस्तुतः इसमें गिरावट आई है। यद्यपि अपने रेंज को बढ़ाकर नए उत्पादों की शुरुआत करके याचिकाकर्ता ने अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने की आशा की थी, तथापि बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण इन वर्षों में याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

100. घरेलू प्रचालनों के संबंध में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का निर्धारण किया गया था। सत्यापित सूचना से निम्नानुसार पता चलता है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08
मांग/ भारत में खपत					
मात्रा	51,308	1,18,500	81,186	94,027	70,520
मूल्य लाख रुपए में	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062
घरेलू उद्योग की बिक्री					
मात्रा	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	203	117	175	175
मूल्य लाख रुपए	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	138	172	233	233
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा					
मात्रा	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	88	74	96	96
मूल्य	**	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	87	74	89	89

101. यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों रूपों में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:

102. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की जा रही आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। आयातित उत्पाद की कीमत और घरेलू उद्योग की कीमत के बीच पर्याप्त अंतर होने के कारण उपभोक्ताओं ने अपनी मांग के एक भाग की पूर्ति आयातित उत्पाद से करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग उन्हीं ग्राहकों को परवर्ती आपूर्तियों में न केवल अपनी कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ है, अपितु बाजार में अन्य ग्राहकों को की गई आपूर्तियों की कीमत में भी कमी की है।

103. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कीमत में नाटकीय ढंग से गिरावट आई है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से मिल रही सतत प्रतिस्पर्धा और व्यापार घाटे के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा उत्तरवर्ती प्रत्येक प्रस्ताव में अपनी कीमत कम की जा रही है। अतः आयातों का भारतीय बाजार में स्पष्ट तौर पर अत्यंत कीमत हासकारी प्रभाव पड़ा है।

लाभ/हानि

104. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री और उसके उत्पादन से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। इन वर्षों में लाभ में आई गिरावट इतनी अधिक रही है कि याचिकाकर्ता को अपने घरेलू व्यापार में जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटा हुआ है।

105. अपने घरेलू प्रचालनों के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभ/हानि का निर्धारण किया गया था। सत्यापित सूचना से निम्नानुसार पता चलता है।:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08 - वार्षिकीकृत	अप्रैल-दिसं. 08
लाभ/हानि/लाख रुपए					
घरेलू	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	(207)	(162)	(964)	(964)
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	(***)	***	***	(***)	(**)
सूचीबद्ध	(100)	64	165	(14)	(14)
बिक्री मूल्य रु./ लाख					
घरेलू	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	138	172	233	233
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	187	302	352	352
बिक्री के % के रूप में लाभ/हानि					
घरेलू	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)

सूचीबद्ध	(100)	(149)	(94)	(412)	(412)
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार	(***)	***%	***%	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	34	55	(4)	(4)

106. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का बिक्री राजस्व बिक्री लागत से लगातार कम रहा है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू प्रचालनों के संबंध में वित्तीय घाटा हुआ है। इसके अलावा, बिक्री राजस्व के प्रतिशत के रूप में घाटा वर्ष 2005-06 में ***% से अत्यधिक बढ़कर जांच अवधि में ***% हो गया है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त वित्तीय घाटा हो रहा था, जिसमें क्षति अवधि के दौरान और अधिक इजाफा हुआ है।

107. चूंकि याचिकाकर्ता के पर्याप्त निर्यात कार्यकलाप हैं, इसलिए घरेलू तथा निर्यात में संयुक्त प्रचालनों में उसका लाभ सकारात्मक बना रहा। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके निर्यात लाभ से इस समय घरेलू घाटे की भरपाई की जा रही है। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि इस आधार पर आगे कोई कंपनी अधिक समय तक प्रचालन नहीं कर सकती। पाटन से घरेलू उद्योग के लिए अत्यंत प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो गई है।

निवेश पर आय

108. चूंकि संबद्ध वस्तु के उत्पादन में मूल निवेश डिजाइन एवं विकास तथा कुशल/योग्य जनशक्ति के संबंध में भौतिक संपदा में किया जाता है, इसलिए याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि लगाई गई पूंजी पर आय के % के रूप में व्यक्ति निवेश पर आय से उस उचित आय का पर्याप्त पता नहीं चलेगा, जितना यह उद्योग आशा करता है। उद्योग ने वैश्विक रूप से सकल मार्जिन के संबंध में लाभप्रदता पर विचार किया है तथा भारत में घरेलू उत्पादकों का सकल मार्जिन उनके वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के सकल मार्जिन से काफी कम रहा है।

109. लगाई गई पूंजी पर आय का निर्धारण घरेलू प्रचालनों के संबंध में किया गया है, जो निम्नानुसार है:

रू./लाख	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08
लगाई गई पूंजी - समग्र कंपनी				
निवल स्थायी परिसंपत्ति	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	180	497	346
कार्यशील पूंजी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	161	249	336
लगाई गई पूंजी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	162	262	318
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	(***)	***	***	***
सूचीबद्ध	(100)	132	285	55
लगाई गई पूंजी पर आय - %	(***)	***	***	***

सूचीबद्ध	(100)	82	109	16
लगाई गई पूंजी - पी यू सी घरेलू	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	120	149	224
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ - पी यू सी घरेलू	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	(179)	(60)	(910)
लगाई गई पूंजी पर आय - %	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	(149)	(40)	(406)

110. लगाई गई पूंजी पर आय में प्रवृत्ति के विश्लेषण से यह पता चलता है कि जहां तक घरेलू प्रचालनों का संबंध है, समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग लाभ नहीं कमा सका है। लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक आय जोक वर्ष 2005-06 में 100 थी, जांच अवधि में और बढ़कर 400 से अधिक हो गई। समग्र कंपनी के लिए आधार वर्ष में घरेलू उद्योग ने घाटा उठाया है। तथापि, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान कंपनी ने लाभ कमाया परंतु जांच अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर आय में पर्याप्त गिरावट आई जो 2% से भी कम हो गई। निर्यात सहित समस्त प्रचालनों पर कंपनी ने निर्यात प्रचालनों के कारण मुख्य रूप से कुछ लाभ कमाया। इन प्रवृत्तियों से स्पष्टतः यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

नकद प्रवाह/लाभ

111. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग के पर्याप्त घरेलू एवं निर्यात प्रचालन हैं, इसलिए घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति से नकद प्रवाह पर पाटन के प्रभाव का पूर्ण रूप से पता नहीं चलता है। अतः घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति का निर्धारण कर एवं मूल्यहास से पूर्व लाभ पर विचार करने के बाद किया गया है। यदि देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का समूची क्षति अवधि के दौरान नकद प्रवाह ऋणात्मक रहा था। इसके अलावा, जांच अवधि में नकद घाटे में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
नकद लाभ - पी यू सी घरेलू	(***)	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	(100)	(211)	(158)	(688)

मालसूची: -

112. विचाराधीन का उत्पादन विस्तृत विनिर्देशन के आधार पर प्राप्त पुष्टिकृत ऑर्डर के बाद ही किया जाता है और ये वस्तुएं मालसूची में नहीं रखी जाती हैं।

रोजगार तथा मजदूरी

113. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि प्रमुख निवेशों में से एक निवेश अनुसंधान एवं विकास के संबंध में बौद्धिक संपदा के विकास में किया जाता है। पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार याचिकाकर्ता ने देश में अभूतपूर्व दूरसंचार वृद्धि के कारण पर्याप्त बाजारी अवसरों की आशा की थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग अपनी वैश्विक उपस्थिति में सुधार कर रहा है जिसके लिए भी गहन अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की जरूरत है। इन सबके लिए जनशक्ति में निवेश अपेक्षित होता है। परिणामतः लगाई गई जनशक्ति और घरेलू उद्योग द्वारा संदत्त परिणामी मजदूरी में इन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा :

क्र. सं.		2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं. 08
1	कर्मचारियों की संख्या				
(क)	अनुसंधान तथा विकास	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	151	247	324
(ख)	अन्य सभी कार्यक्रम	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	139	178	211
(ग)	सकल रोजगार	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	145	215	272
2	मजदूरी				
(क)	अनुसंधान तथा विकास (रु./लाख)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	181	281	226
(ख)	अन्य सभी कार्यक्रम (रु./लाख)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	166	271	260
(ग)	सकल रोजगार (रु./लाख)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	174	276	242

114. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि रोजगार में कमी करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे किसी प्रयास का तात्पर्य घरेलू उद्योग की स्थायी गिरावट की प्रक्रिया से लगाया जाएगा। विदेशी उत्पादकों की मंशा बिल्कुल साफ है अर्थात् इस प्रमुख उत्पाद खंड में भारतीय उद्योग को समाप्त करना। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस देश में विचाराधीन उत्पाद का उन्होंने विकास किया था और भारत इस उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद की क्षमता और सामर्थ्य रखने वाले विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था। भारत में दूरसंचार वृद्धि के कारण विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई है। भारतीय उत्पादक की समाप्ति से न केवल भारत में विदेशी उत्पादकों के लिए भारी बाजार अवसर उपलब्ध होंगे, अपितु विश्व बाजार में उनके लिए प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो जाएगी। अतः वर्तमान पाटन का रोजगार एवं मजदूरी पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि भारत मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने और प्रौद्योगिकीविदों के सुविज्ञ पूल का सृजन करने का प्रयास कर रहा है जो उच्च मूल्य, बौद्धिक संपदा एवं उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं।

115. याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि चीन की सरकार द्वारा अनेक तरीकों से दूरसंचार उपकरण विनिर्माण उद्योग की सहायता की जा रही है जिसमें भारी मात्रा में सुलभ ऋण भी शामिल हैं ।

उत्पादकता:

116. घरेलू उद्योग की उत्पादकता का आकलन नगों के रूप में व्यक्ति प्रति कर्मचारी उत्पादन तथा उत्पादित एस डी एच उपकरणों के मूल्य के संबंध में किया गया है ।

क्र.सं.		2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसं.08
1	प्रति कर्मचारी उत्पादन				
(क)	उपकरणों की संख्या - घरेलू उद्योग	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	140	54	48
(ख)	उपकरणों का मूल्य - घरेलू उद्योग (लाख रुपए)	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	97	81	66

117. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है । तथापि, उत्पादकता में सुधार के बावजूद कीमत मापदंडों में पर्याप्त गिरावट आई है ।

निधियों को जुटाने की क्षमता:

118. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश वर्तमान मामले में कोई निर्णायक कारक नहीं है । वस्तुतः इस उद्योग में निधियों की जरूरत नियत परिसंपत्तियों के बजाए कार्यशील पूंजी के कारण अधिक होती है । अतः निधियां जुटाने में इस उद्योग की क्षमता पर घरेलू उद्योग के वर्तमान स्तर की लाभप्रदता के साथ गंभीर प्रभाव पड़ सकता है ।

वास्तविक क्षति के बारे में निष्कर्ष

119. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए प्रारंभिक निर्धारण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सबद्ध आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है । क्षति अवधि के दौरान आयात कीमत में पर्याप्त गिरावट आई है । आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है । आयातों से बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमत में हास हो रहा है । लाभ, बाजार हिस्से, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, माल सूची एवं वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है यद्यपि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन एवं बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है, तथापि बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री करने में घरेलू उद्योग ने व्यापार के पर्याप्त अवसर गंवाए हैं । लाभ, निवेश पर आय एवं नकद प्रवाह में गिरावट निर्यात मोर्चा पर निष्पादन में पर्याप्त सुधार आने के कारण आई है । रोजगार,

उत्पादकता और मजदूरी में सुधार हुआ है । तथापि, इनमें हुए सुधार से अन्य मापदंडों में गिरावट कम प्रदर्शित हुई है । वर्तमान अवधि के दौरान निष्पादन में आई गिरावट काफी अधिक और वास्तविक रही है ।

कारणात्मक संबंध

120. वास्तविक क्षति की मौजूदगी तथा कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री एवं कीमत ह्रासकारी तथा न्यूनकारी प्रभावों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा एवं मूल्य संबंधी प्रभावों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने इस बात की भी जांच की है कि क्या भारतीय नियमों एवं पाटनरोधी करार में सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है । अतः निम्नलिखित मापदंडों की जांच की गई है ।

क) तीसरे देशों से आयात :- जो देश जांचाधीन नहीं है उन देशों से हुए आयात या तो नगण्य हैं, या फिर उनकी कीमत संबद्ध देशों से हुए आयात की कीमत से अधिक है और इसलिए इनका घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता है;

ख) मांग में कमी: - क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है । अतः मांग में संभावित कमी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता ।

ग) खपत की पद्धति: - किसी भी हितबद्ध पार्टी ने खपत की पद्धति में किसी खास परिवर्तन का आरोप नहीं लगाया है ।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां: - यह वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है । आवेदक संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक है और वह घरेलू उत्पादन के लगभग 100% का उत्पादन करता है । अतः घरेलू प्रतिस्पर्धा को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता । प्राधिकारी की जानकारी में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों का कोई अन्य साक्ष्य नहीं लाया गया है ।

ड) प्राद्योगिकी विकास :- प्रौद्योगिकी में खास परिवर्तन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन :- रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि घरेलू उद्योग के निर्यातों का उसके निष्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है ।

छ) उत्पादकता: - कुल उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है । अतः इसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता ।

121. उपर्युक्तानुसार कारणोत्तर विश्लेषण से यह पता चलता है कि पाटित आयातों से इतर किसी अन्य कारक का घरेलू उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ा है ।

कारणात्मक संबंध को स्थापित करने वाले कारक

122. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तविक गिरावट आई है। अतः निम्नलिखित आधारों पर पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि होती है :

क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कीमत और परिणामतः आयातों की पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट आई है जिससे कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है। इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ था।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री कीमत में कमी किए जाने का कंपनी के लाभ, नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ग. यद्यपि, घरेलू उद्योग ने आयात कीमत में गिरावट का मुकाबला किया है, तथापि अत्यधिक सकारात्मक कीमत कटौती के कारण संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

घ. मांग में वृद्धि और घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री कीमत में कमी के बावजूद आयातों की पहुंच कीमत में अत्यधिक कमी के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इससे घरेलू उद्योग की वृद्धि अवरुद्ध हुई है।

ङ. विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित अत्यंत कम कीमतों से घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री को उस स्तर तक बढ़ाने से वंचित हुआ है, जिस स्तर तक वह पाटन के अभाव में बढ़ा सकता था।

123. अतः प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध देशों/क्षेत्रों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

124. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। यह तुलना भारत में आयातित मॉडल की क्षति रहित कीमत के निर्धारण द्वारा की गई है। आयातित प्रत्येक मॉडल के लिए अलग-अलग तुलना की गई है और क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात् संबद्ध आयात मात्र पर विचार करने के बाद भारत औसत क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है:

देश	निर्यातक	क्षति मार्जिन रूपरेखा प्रति नमूना	क्षति मार्जिन %
चीन जन. गण.	मै. फाइबर होम टेलीकम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि.	***	250%-260%
	एल्काटेल-लुसेंट शंघाई बेल कंपनी लि.	***	25%-35%%
	मै. हुआवी टेक्नो. कंपनी लि.	***	50%-60%

	मै. हैंगझाऊ ई सी आई टेलकॉम. कंपनी लि.	***	95%-105%
इजराइल	मै. ई सी आई टेलकॉम. लि., इजरायल	***	नकारात्मक

निष्कर्ष

125. हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा किए गए अनुरोधों और इस जांच परिणाम में दर्ज किए गए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु ने निर्यातक देश के घरेलू बाजारों में उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेश किया है;
- संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन अत्यधिक और न्यूनतम सीमा से अधिक है;
- घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को हुई यह क्षति संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभाव, दोनों के कारण हुई है।

भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आम तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त कराना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं होंगे, अतः उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सिफारिशें

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत कर उसकी सूचना समस्त हितबद्ध पार्टियों को दी गई थी और पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। निर्धारित नियमों के अनुसार, पाटन, क्षति तथा पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की प्रारंभिक जांच शुरू कर उसे संपन्न करने के बाद तथा संबद्ध देशों के खिलाफ सकारात्मक पाटन मार्जिन की अनंतिम पुष्टि करने एवं यह निष्कर्ष निकालने के बाद घरेलू उद्योग को ऐसे पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है, प्राधिकारी का यह मत है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की रोकथाम करने के लिए अनंतिम उपाय लागू करना अपेक्षित है।

128. अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों पर निम्नलिखित प्रपत्र में और ढंग से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

129. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन जो कम हो, के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो सके। तदनुसार संबद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई शुल्क तालिका के कालम 9 में किए गए उल्लेख के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क, जो आयातों के सीआईएफ मूल्य का प्रतिशत होगा, लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप-शीर्ष	विवरण	उद्गम देश	निर्यात देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	851762	"पूर्ण एस डी एच उपकरण जिसमें सीकेडी/एसकेडी रूप शामिल है और जिसमें उसके पुर्ज तथा संघटक शामिल हैं, जिनका उक्त उपकरण के लिए अन्य उपयोग होगा है"	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मै. फाइबरहोम टेलीम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि.	मै. फाइबरहोम टेलीम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजीज लि.	236%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	अल्काटेल-लुसेंट शंघाई बेल कंपनी लि.	अल्काटेल-लुसेंट शंघाई बेल कंपनी लि.	25%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मै. हुआवी टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.	मै. हुआवी टेक्नोलॉजीज कंपनी लि.	50%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	उपयुक्त क्र.सं. 1,2 व 3 से इतर कोई अन्य संयोजन	कोई	236%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	इजराइल	मै. हैंगझाऊ ई सी आई टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी लि.	मै. ई सी आई टेलकॉम लि., इजराइल	93%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	इजराइल	उपयुक्त क्र.सं. 5 से इतर कोई अन्य संयोजन	कोई	236%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
7	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	इजराइल से इतर कोई	कोई	कोई	236%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
8	-वही-	-वही-	कोई	चीन जन. गण.	कोई	कोई	236%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
9	-वही-	-वही-	इजराइल	इजराइल	मै. ई सी आई टेलकॉम लि., इजराइल	मै. ई सी आई टेलकॉम लि., इजराइल	NIL	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
10	-वही-	-वही-	इजराइल	इजराइल	उपयुक्त क्र.सं. 9 से इतर कोई अन्य संयोजन	कोई	37%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
11	-वही-	-वही-	इजराइल	इजराइल से इतर कोई	कोई	कोई	37%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %
12	-वही-	-वही-	कोई	इजराइल	कोई	कोई	37%	आयातों के सीआईएफ मूल्य का %

आगे की प्रक्रिया

130. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- क. प्राधिकारी समस्त हितबद्ध पार्टियों से इन जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा;
- ख. प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता और संबंधित समझी जाने वाली ज्ञात अन्य हितबद्ध पार्टियों को अलग से लिखा जा रहा है, जो पत्र के प्रेषण की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इस जांच परिणाम के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है;
- ग. प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे और सत्यापन किया जाएगा;
- घ. प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2009

Preliminary Findings

Sub. : Anti-Dumping Investigation involving import of Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment originated in or exported from China PR and Israel.

F. No. 14/2/2009-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof:

2. WHEREAS M/s Tejas Networks Limited (herein after referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as this Authority), in accordance with the Act, and Rules, alleging dumping of Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment (herein after referred to as subject goods), originating in or exported from the Republic of China and Israel (referred to as subject countries) and requested for initiation of an investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods.

3. AND WHEREAS, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 21st April 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries in accordance with the sub-Rule 5(5) of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Procedure

4. Procedure described below has been followed with regard to this investigation after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority.

- (i) The Designated Authority sent copies of initiation notifications dated 21st April 2009 to the Embassies/representatives of the subject countries/territories in India, known exporters from the subject countries/territories, importers and the domestic industry as per the information available with it and requested them to file questionnaire responses and make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- (ii) Copies of the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry were made available to the known exporters and the Embassies/High Commissions of the subject countries/territories in accordance with Rules 6(3) supra.
- (iii) The Embassies/High Commissions/ Representatives of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries/territories to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, non confidential version of the petition and exporter questionnaire sent to the exporter was also sent to the Embassies/High Commissions of subject countries in India along with a list of known exporters/ producers made available by the petitioners.
- (iv) The Authority sent questionnaire to following known exporters/ producers of product concern in subject countries, to elicit relevant information, to the known exporters from subject countries in accordance with the rule 6(4).
 1. Huawei Technologies Co. Limited
 2. Wuhan Research Institute of Post & Telecommunication.
 3. ZTE Corporation
 4. ECI Telecom
- (v) In response to the above notification following exporters from the subject countries filed their questionnaire responses:
 1. ZTE Corporation Ltd.
 2. Huawei Technologies Co. Ltd.
 3. Shenzhen Huawei Technologies Ltd.
 4. Hisilicon Technologies Ltd.
 5. Fiberhome Telecommunications Technologies Co. Ltd.
 6. Wuhan Fiberhome International Technologies Co. Ltd.
 7. Hangzhou ECI Telecommunications Co. Ltd.
 8. ECI Telecommunications Co. Ltd.
 9. Alcatel Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.
- (vi) Apart from this China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & electronic Products "CCCME" has also filed a representation, which has been taken on record.
- (vii) Questionnaires were also sent to following known importers and Consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rule 6(4).

Aircel Limited
Dishnet Wireless Limited
Bharati Airtel Limited
Bharat Sanchar Nigam Limited

Prathvi Information System
Punjab Communications Limited
HTL GST
Huawei India

Tata Teleservices Limited	ZTE India
Tata Teleservices (Maharashtra) Limited	ECI India
Idea Cellular Limited	Alcatel Lucent
Vodafone Essar Limited	Nokia Siemens Networks
Railtel Corporation of India Limited	Ericsson
Tata Communications	Himachal Futuristic Communications
Reliance Communications Limited	ICOMM
Shyam Telelinks	

- (viii) Followings have responded to the questionnaire:
1. ECI India Pvt. Co. Ltd.
 2. Huawei India Telecommunications Pvt. Ltd.
 3. Vodafone Essar Ltd.
 4. Vuppalamritha Magnetic Components Ltd.
 5. Prithvi Information's Solutions Ltd.
- (ix) That apart, submissions on various aspects of the case have also been made by ELP on behalf of ECI and Lakshmi Kumaran and Shridharan in behalf of Aircel. However these submissions were made nearly two months after the last permissible extended date, as fixed by the Authority, and therefore, have not been considered for the purposes of Preliminary Determination.
- (x) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations;
- (xi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file and kept open for inspection by the interested parties;
- (xii) Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the petitioner on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out provisionally so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- (xiii) The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, alongwith non-confidential summary thereof, has been treated confidential (***) in this finding represents information furnished by the domestic industry on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xiv) Investigation is carried out for the period starting 1st April – 31st Dec 2008 (9 months-POI) and injury is examined for 2005-06, 2006-07, 2007-08 and POI.
- (xv) SDH equipment is normally sold in numbers. However, it can be imported either as assembled product or in CKD/SKD conditions. Associated costs and price of different SDH equipments varies significantly.

Product under Consideration and Like Article

5. The product under consideration in the present investigation is "Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, its accessories, associated software and its essential parts & components, in assembled, CKD, SKD form or fitted with eventual broadband/cellular equipment".

6. SDH transmission equipments are also known as multiplexers, Add Drop Multiplexers (ADM), Multiple Add Drop Multiplexer (MADM), digital cross-connects. Populated PCBs, Power supply, Lasers, Chassis and software meant for SDH transmission equipment, etc. consist of essential parts of a SDH transmission equipments and are within the scope of the product under consideration provided the said components are meant for SDH transmission equipment application only.

7. SDH transmission equipments can be bought either as transmission equipments or forming part of another equipment e.g., broadband and/or cellular (both GSM and CDMA) equipment. SDH transmission equipments forming part of broadband and/or cellular equipment are also within the scope of the product under consideration.

8. Product under consideration is essentially an assembly of a number of electronic components and/or electronic printed circuit boards, designed to perform the intended function of multiplexing for combined lower speed signals into high speed signals for transmission through optical fiber over short or long distances. Since, among other applications, these are installed at Base Transmission Stations, switch exchanges and other point of presence, SDH equipments installed at different locations may differ in terms of the associated properties. Different SDH equipment are comparable in term of essential product characteristics including physical and optical, production technology, manufacturing process, R&D Development, software capabilities, functions and usage, etc. Accordingly, various SDH equipments have been regarded as one like product for the purpose of present investigation.

9. The product under consideration can be imported either as complete equipment, or in CKD, SKD form. Further, a number of accessories are required for connecting/installing SDH transmission equipment in the network (E1 cables, PCM cables, power cables, racks, workstations etc.). Software is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. These all are also within the scope of the product under consideration.

10. It is noted that there are a number of components required for production of the product under consideration which have multiple alternate usage. It is therefore, clarified that with regard to the components, the scope of PUC is only such components and parts having a dedicated application with regard to the PUC alone. In other words, the scope of the product under consideration extends to components/parts only if the same have a dedicated use in production of SDH equipment.

11. The product under consideration is classified under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975. It is further classified under the heading 851762 of schedule-I of Custom Tariff Act as per Indian Trade Classification. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Standing of the Domestic Industry
Submission by the domestic industry

12. The petitioner has determined production of other Indian producers based on information published in Voice and Data Recorder magazine, which has been appropriately adjusted in order to determine information for the product concern.

13. The petition was supported by M/s. Measurement & Controls Limited.

14. The petitioner's production constitutes a major proportion in Indian production of the subject goods. The petition satisfies the requirement of standing under the Rules.

15. Letter from CMAI clearly stated that the petitioner account for a major proportion in Indian production.

16. The petitioner should be considered as eligible domestic manufacturer to bring the present petition, notwithstanding that supplemental imports of components or sub- assemblies being made by them;

17. Other entities are undertaking only incremental activities in India and are ineligible domestic manufacturers for the reasons (i) they are not undertaking production activities in India sufficient enough to constitute substantial transformation of the input into the output, (ii) these companies should in any case be considered ineligible, given that they are substantially importing the product under consideration and/or are related to foreign producers of the subject goods from the subject countries. Focus of these companies' remains on imports with supplemental assembly line or testing operations in India.

18. Various suppliers of SDH equipment in the Indian market can be categorized into 2 categories

- a. Companies who undertake full product life-cycle related expenses, including technology development, research & development and manufacturing in India
- b. Companies who undertake major product related expenses, including technology development, research & development and manufacturing outside India and export finished product either in assembled or CKD/SKD condition to India along with the final assembly/testing instructions

19. The table below gives bifurcation of materials consumption by Tejas during Period of investigation.

Financial Numbers in Crores	Total value	%age
Value of goods sold (COGS)	***	
Expenses on R&D	***	***
Raw materials consumed	***	***
Manufacturing Overheads	***	***
SG&A and other Expenses	***	***
Total Raw Material Purchased	***	***
Domestic raw materials Purchased	***	***
Imported Raw Materials Purchased	***	***
Raw materials break down		
<input type="checkbox"/> Imported raw materials	***	***
<input type="checkbox"/> from China	***	***
<input type="checkbox"/> From Israel	***	***
<input type="checkbox"/> from other countries	***	***
Capital employed		
<input type="checkbox"/> Net Fixed Assets	***	
<input type="checkbox"/> Net Fixed Assets Deployed in R&D	***	***
<input type="checkbox"/> Net Fixed Assets Others	***	***
Capital		

20. A statement showing country wise purchases is given below.

Place	Amount	% of total purchases
Thailand	***	***
India	***	***
Singapore	***	***
China	***	***
Taiwan	***	***
Japan	***	***

Hong Kong	***	***
USA	***	***
United Kingdom	***	***
Switzerland	***	***
Israel	***	***
Dubai	***	***
Canada	***	***
Malaysia	***	***
Germany	***	***
Philippines	***	***
France	***	***
Grand Total	***	

PURCHASE ANALYSIS

Total value of Domestic	874,261,252	34.42%
Total value of Imports	1,665,890,195	65.58%
	2,540,151,447	

21. It would be seen that the while value of raw materials is****% of total cost of production, value of Chinese parts/components imported by the petitioner is just ****% of total raw materials purchases (i.e., just ****% of total costs).

22. Table below gives breakdown of parts/components imported from China.

Commodity	Total (Rs.)	% of total purchases	% of total cost of production
Transceivers	***	***	***
Bareboard	***	***	***
Patch Cord	***	***	***
Misc	***	***	***
PCBA (made to order item)	***	***	***
Capacitor	***	***	***
Connectors	***	***	***
Grand Total	***		

23. Except printed circuit boards, the parts/components imported from China are parts/components which do not have dedicated applications in the product under consideration/ As regards printed circuit boards, not only that the value of the imports is insignificant, but also these were produced as per petitioner's technology.

24. Table below provides the financial breakup of Manufacturing Operational activities of Tejas.

"Like Products" related Operational Activities	Cost in Rs. Crores	% Share of Operational Cost
Research Design and Development Expenses	***	***
Manufacturing Expenses Including Testing and Assembly	***	***
Total	***	***

25. Table given below compares the various activities done by Tejas and Importers. As is evident, Prithvi, VMPL merely carry out assembly operations in India. Huawei does most of its Operations outside India.

Activities	Tejas	Prithvi	VMPL	Huawei
Research in India with IPR resident in India	Yes	No	No	No
Design and Development in India	Yes	No	No	No
EMS Contract Manufacturing in India and Other Countries	Yes	No	No	No
Assembly & Test Procedure "Specifications Development" in India	Yes	No	No	No
Final Assembly & Testing in India	Yes	Yes	Yes	No
Post Sales "bug fixes /enhancement /upgrades" done in India	Yes	No	No	No
Post Sales – Spares Supply/ Technology Support in India	Yes	No	No	Yes

Submissions by opposing interested parties.

26. Huawei Technologies Ltd. has submitted that applicant itself is an importer of the subject goods and has no locus of filing the present petition as the applicant gets significant parts of components outsourced to specialized producers called EMS. CCME has also raised a similar objection regarding standing.

27. Huawei has furthermore submitted that the applicant has been importing subject goods from Celestica, an EMS, which operates through numerous offices in China PR. Since the applicant has itself imported the goods from subject countries, it cannot represent "domestic industry" in this case.

28. Huawei has also put forth that the applicant's claim for qualification for "Domestic Industry", based on the criterion of R&D is defective since R&D is not the sole factor to be used in this regard.

29. Reference is given of paras 7.112, 7.114 and 7.124 of WTO Panel Report WT/DS/337/R. These paras deal with the interpretation of Article 4.1 of the Anti-Dumping Agreement. It has been thereby contended that all categories and group of producers shall be considered as forming domestic industry.

30. Huawei has also claimed that Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), a Public Sector Undertaking also classifies the applicant as an Importer.

31. Petition pertains to some products STM 256, STM 64 and Digital Cross Connects. These are such products which the applicant neither manufactures nor sells. Therefore also it has no Locus.

32. CCCME disputed the applicant's claim of having 84.7% share in Indian production during the POI and applicant does not meet the standing requirements.

33. No proof is given for claim that M/s Measurement & Controls Limited supports its petition.

34. The 'Letter of Undisclosed Association' has wrongly classified MCI, BEL and ITI as Indian Producers. MCI has not even sold single unit of subject goods till date. BEL and ITI work on the same model as HFCL and Prithvi Ltd.

Examination by the Authority.

35. Petitioners have filed a letter from CMAI (Association) who have confirmed that the petitioner account for a major proportion of total Indian production.

36. Authority notes that the reference is given by the opposing parties to panel report in the matter concerning Farmed Salomon from Norway. Authority however, notes that the facts of that case are different than those of the present case. In the stated case, EC had not examined whether or not activity conducted by those producers, who were not considered as producers of product concerned, was an activity which could constitute production.

37. Authority notes that the reference is given by the opposing parties for panel report in the matter concerning Farmed Salomon from Norway. Authority however, notes that the interpretation of Art. 4.1 given by the WTO Panel has a limited scope as the same was based only upon the plain language of Article. The para 7.115 of the Report is relevant in this regard:

7.115 There is no dispute that filleted salmon is within the scope of the like product identified by the EC in this case. Thus, based on our interpretation of the plain language of Article 4.1, we consider that any enterprise that produced any form of the like product should be considered, at least in the first instance, a "producer" of the like product, and as such, part of the domestic industry.

Footnote 289 reads as follows:

289. There may be circumstances in which an enterprise whose product is within the scope of the like product may be found to have engaged in a level of activity so low as to justify the conclusion that it did not, in fact, "produce" the like product. However, there was no consideration of the degree of activity of filleting-only undertakings in defining the domestic industry during the investigation. Therefore, the question is not before us on the facts of this case. (Emphasis Supplied.)

38. Penal has therefore kept some circumstances as mentioned in the footnote 289, outside the scope of its interpretation of Article 4.1. Therefore, the panel decision does not cover a situation where in an enterprise whose product does fall within the ambit of like product if involved in an activity which is either not very significant or is very minimal so as to determine its standing as a part of 'domestic industry'.

39. Authority notes that the petition has been filed by Tejas Networks Limited and supported by Measurements and Controls Limited. Prithvi, VMPL and Huwai claimed that these companies should be considered as "domestic industry". The information provided by these companies was carefully examined in the light of the legal provisions. The Authority notes that there are two issues in this regard (a) whether the company can be considered as a producer, and (b) whether the company should be considered "eligible" domestic producer. Rule 2(b) provides as under in this regard –

(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry:

40. The Authority notes that there are certain instances when a domestic producer may not be deemed to form part of domestic industry. Domestic industry argued that a company can be recognized as a producer only when it undertakes so significant production activities that the inputs undergo "substantial transformation". Petitioner disputed claim of these companies as a "producer" stating that these companies are not undertaking so significant production activities that these can be considered domestic producer on the basis of "substantial transformation". The Authority however holds, without disputing the claim of these companies as an Indian producer that these companies have themselves conceded that they are engaged in assembly line operations by importing the subject CKD, SKD or parts / components required for production of the subject goods from subject countries. Since the scope of the product under consideration in this case includes CKD, SKD and components so long as the same are used in production of the product under consideration, it is evident that these companies are substantially importers of the product under consideration itself. Since these companies are substantially importing the product under consideration itself in its CKD, SKD or component form, these companies are in any case required to be excluded from the scope of "domestic industry".

41. Petitioner alleged, based on annual reports of VMCL and Prithvi that the two companies are closely related to each other. The annual report of Prithvi, in its disclosures relating to related party transactions, has reported VMCL as a related party.

42. VMCL has not filed questionnaire response in the form and manner prescribed, either as a domestic producer or an importer of the product under consideration. However, it is found from the legal arguments/submissions made by the company that the company's operations are quite similar to Prithvi. The Authority therefore holds that VMCL has not fully cooperated with the Authority, even when its related company has provided questionnaire response. Further, the company has provided no information to establish that it is entitled to be treated as a domestic producer.

43. The Authority carried detailed investigations at the premises of the petitioner. It was observed that the petitioner has made significant investments in manpower as well as plant and equipments and has all the required capabilities starting from research and development, production, assembly, testing and post-sales support. The petitioner was directed to provide information with regard to imports made by them, regardless of the source. Further, the petitioner was directed to provide information with regard to all parts/ components. The Authority notes that –

- i. The petitioner has not imported any SDH equipment during the entire reference period from subject countries;
- ii. The petitioner has imported certain parts/components meant for production of SDH equipment. These parts/components have been sourced from China and third countries. There are no imports from Israel.
- iii. Since there are no imports of completed SDH equipment, to that extent Rule 2(b) is not attracted and the petitioner cannot be considered as an importer of the subject goods. However, since the scope of the product under consideration extends to parts/components when meant for SDH application as well, the imports of parts/components by petitioner becomes relevant. Imports of parts/components from third countries, i.e. other than China/ Israel is wholly

irrelevant and do not come within the purview of imports as defined under Rule 2(b). The verified information shows that in terms of components, the petitioner has imported dual use components / parts, as well as those components and parts which have a dedicated use for SDH equipment. It is noted that total imports from China with regard to the components made by the petitioner during POI is 4.79% of the total cost of production out of which only 0.53% are such components /parts which have a dedicated use for SDH equipment whereas all other components/parts have a dual use and are outside the scope of proposed measures.

44. Barring allegation of imports per se, no other reasons / grounds have been advanced by the interested parties justifying exclusion of petitioner as eligible domestic industry. The Authority holds that principal activity of the company is manufacturing in India, which includes essential research and design and development in production activity. The petitioner has not reduced, its own production activity, and has not turned to trading. No justifiable reasons have been advanced by the interested parties warranting exclusion of the petitioner and, therefore, the Authority holds that it will not be appropriate to exclude the petitioner from the scope of eligible domestic industry.

45. In view of the above, having regard to the definition of the domestic industry under Rule 2(b) and information on record, the authority is unable to consider VMPL, Prithvi and Huawei as eligible domestic industry for the purpose of present findings.

46. Based on the information available on record of the Authority, provisionally determines that:

- a. Production by the petitioner constitutes production for the purpose of the present investigations;
- b. Imports by the petitioner are not such as to disqualify the petitioner from the scope of Rule 2(b).
- c. Imports by other domestic suppliers such as Prithvi, VMPL and Huawei are such as to render them ineligible domestic producers under Rule 2(b).
- d. Production of the petitioner accounts for a major proportion of total Indian production.

47. In view of the above, Authority concludes that the petition satisfies the standing and the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

Other submissions and issues raised

48. Followings are the other issues raised by other interested parties.

- a. Applicant has either not provided required information or not provided in prescribed format. Imports have not been furnished in proper manner, Source of imports and period thereof is not given.
- b. It is not clear, whether import data is based on sales realized or contracted. No bifurcation of sale to India and export sales is given in Proforma IVA of the Petition.
- c. Sales other than subject goods have also not been provided in unit (Number) terms.
- d. As per petitioner's own annual report & data applicant's Market Share has increased, and therefore the imports of subject goods have no consequential negative impact on applicant's performance.

- e. The PCN classification as it does not reflect the characteristics of concerned product.

Examination by the Authority

49. Authority notes that a number of allegations have been made by the various parties regarding petition filed by the domestic industry. Regarding imports in prescribed format, source and period, Authority notes that the petitioner has given transaction wise information of imports of product concerned in India along with the source document of imports for previous years. In Proforma IV-A, indexation of exports sales is also given. Petitioner is required to give only sales of product concerned in IV A and not for other products. Regarding PCN system, interested parties have not established how and why the PCN system is incorrect and what should be the various parameters defining the product. At the same time, the interested parties have given PCN-wise information in the response filed.

Confidentiality

Submissions made by domestic industry

50. Domestic industry has commented on confidentiality claimed on PCN exported to India by various responding exporters by making following submissions :

- (i) PCN or product type exported to India relates only to the product sold in Indian market. The type of product exported to India cannot, by any stretch of imagination be business sensitive information.
- (ii) As stated in the petition, consumers typically seek offers from various suppliers. Therefore, various suppliers are precisely aware of specific requirement of each of the customers. To such an extent, various players in the market know product exported by various suppliers.
- (iii) Even if it is considered that the information relating to specific product type sold to a particular customer could be sensitive, in any case the product description itself cannot be business sensitive. At worst, the Designated Authority could permit confidentiality on name of the customer concerned.
- (iv) By withholding the information with regard to the PCN type, the interested parties have effectively attempted to impede the process of investigation. The purpose of PCN system is to allow fair comparison between – (a) normal value and export price; (b) landed price of imports and selling price of the domestic industry; and (c) landed price of imports and non injurious price of domestic industry. Unless PCN supplied by various parties are made known to parties, the domestic industry is unable to make injury submissions without knowing the product types exported by the foreign producers.
- (v) They have further drawn the attention to rule 7 providing that if the Authority is not satisfied on the claim of confidentiality made by the interested parties the Authority shall reject such information. They have further stated that in a situation where the interested parties claim excessive confidentiality the domestic industry is prevented from participating in the investigation and responding to the questionnaire response filed by the exporters.

Submissions made by Responding exporters

ECI Telecom Limited, Israel and HETC, China PR.

51. They have submitted as follows :

- (i) On the issue of disclosing the PCN's, we would like to submit that this information as regards the PCN structure as was presented by the Petitioner in the Non-Confidential Petition along with the additional parts / assemblies not covered in the Petitioner list has been already made available in the Non-Confidential Petition filed by the Exporters vide our communication dated July 17, 2009.
- (ii) The PCN structure submitted by the Exporters covers all the imports of the parts / components which have been exported during the Period of Investigation in consonance with the PCN structure presented by the Petitioner and as requested by the Hon'ble Designated Authority.
- (iii) This information is in keeping with the standard of disclosure made by the Petitioner. Consequently it is submitted that the quality and the nature of the information as made available by the Exporters meets the standards and transparency of the information made available by the Petitioner in the Non-confidential Petition.
- (iv) Further, it is an established fact that no end-user order products based on PCNs Orders are placed on the basis of system configurations and features. The entire PCN exercise has been undertaken to facilitate this anti-dumping investigation. Detailing PCNs based on configurations ordered by the Petitioners will compromise the position of the actual users, as well as our client's position in pricing. In fact, the Petitioners are well aware of the parts/components exported by the subject countries into India as sourced by IBIS and relied upon in the Petition. In any case, the Exporters do not export PCN /product type. The Exporters only exports parts/components/assemblies on the request of the request of the private telecom companies and not PCN /product type as alleged by the Petitioner. The information being sought by the petitioner will lead to the disclosure of the types/configurations of equipments exported during the Period of Investigation and given the oligopolistic nature of the buyers in this market; it will be easy to correlate the export to the buyer. In fact this has been confirmed in paragraph 9ii) of the letter dated 30th July, 2009, from the Petitioner's consultant.
- (v) There is no information which has been withheld by the Exporters that impedes the investigation. The PCN has been structured on the same basis as requested by the Hon'ble Designated Authority.
- (vi) It is submitted that the Petitioners cannot interject at this stage to intervene in the affairs of the Hon'ble Designated Authority. The Exporters have reposed their faith in the Hon'ble Designated Authority who has the requisite experience to calculate the dumping as well as injury margin. If there is any difficulty being faced by the Petitioners in making submissions without knowing the product types, the onus is firstly on them to disclose the same level of information to the interested parties and that too during the time of the initiation. The Petitioners have failed to provide this information to the interested parties and is clearly exceeding the confidential rights of the interested parties as enshrined under Rule 7 of the Indian Anti-dumping Rules.

52. The Authority had also sought details on BOM relied upon by the Exporter for cost of production as detailed in Appendix 8. The same has also been provided in respect of both the companies separately in the form of a soft copy vides E.Mail dated 24.8.2009 and has been taken on record.

M/S Huawei Technologies Co., Ltd. China PR

53. They have not furnished any written comments to the issue of confidentiality but have provided a revised non-confidential version of the response, disclosing the PCN details. They have however failed to provide BOM details as called for.

M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China PR

54. They have disclosed the PCN details and to this effect provided a soft as well a hard copy of the same. The same has been placed in public file. They have also provided the BOM details which has been taken on record.

M/S ZTE Corporation China PR

55. They have responded to the Authority on this issue by stating as under.

- (i) As to the Company, During the POI, its products with the same PCN or product type exported to India was exported to other customers at home and abroad. Whereas, due to the known characteristics of SDH products, there are so many types of SDH products extraordinarily similar, especially in components with the description thereof, with the types exported to India, what's more, the different products sold in different market to different customers must be a reflex of the different market positioning and strategy of company. Based on the foregoing, once the PCN or types exported to India is disclosed to the petitioner, the petitioner can easily recognize the Company's market positioning strategy, even can estimate the cost of price of the PCNs or types exported to India as showed in its petition (the "Petition"), which are all sensitive business information in any stretch of imagination, with a seriously adverse influence on fair competition on SDH products in India market.
- (ii) Even though the Company is precisely aware of specific requirement of each customer, all the business information in a specific contract signed by customer with its supplier, such as type, description and pricing consultation must be sensitive business information prescribed in the term of confidentiality of the contract. Due to which, except the parties of a contract, no other players in the market know product exported by various suppliers. The petitioner's request to disclose the types information is a pretty powerful evidence of that the aforesaid business information are confidential to the petitioner, i.e., not public to "various players" as the petitioner said in its request. In line with the foregoing practice and theory, should the information, relating to the Imports details, Dumping Margin Calculation, and Price Undercutting of PCNs and types of SDH products exported to India from China on page No.46-48, No.78-81 and No.84-89, is not precise, the petitioner may be involved in fabricating import information for the undergoing investigation against exporters of China; or, the petitioner may be suspected of being involved in illegally obtaining sensitive business information. So hereby, we request the Designated Authority to direct the petitioner to disclose the origin as well as the authority of employment of the aforesaid information in its Petition. Above all, since it has been aware of the sensitive business information as indicated on the aforesaid pages, we wonder why the petitioner is blind to the information it has employed in the Petition, and raises a new request for the same information.
- (iii) The product description of the export from China as the petitioner employed in the Petition is sensitive business information in any sense. For each exporter, the specification and composition of the products are embodied in the description, which also indicates one company's marketing strategy or market positioning in India.

Therefore, if the description is disclosed, the petitioner shall obtain some sensitive business information not Indispensable to the undergoing investigation. Meanwhile, it's well known that Indian network operators as the Company's clients purchase SDH products in the way of "list purchase", which can prevents the competitors of the Company to acquire the specific characteristics of its network. If the PCNs get public, the network characteristics of Indian operators shall be disclosed as a material confidentiality, the network characteristics of Indian operators shall be disclosed as a material confidentiality, which will be unacceptable to the Company and the aforesaid operators as a fair competitor in India market.

- (iv) It has come to our attention that on page No.76 of the Petition, the petitioner has achieved to calculate the dumping margin as well as the normal value, export price, and on page No.84-89 of the Petition, the petitioner has achieved to calculate the price undercutting as well as the landed price, imported price and value. Whereas, the petitioner has never provided any information about PCNs, types or description of its products. For the paralleled involvement in the undergoing investigation, we request, at the same time, the Designated Authority to direct the petitioner to disclose the PCNs or types with the description of its products, failing which, the petitioner shall impede the process of the undergoing investigation.
- (v) In view of the foregoing, we believe the Company has been pursuant to the Rule and hasn't impeded the process of the undergoing investigation. For the stake of confidentiality interest of the exporters of China including the Company, the Designated Authority are requested to refuse the petitioner's request for disclosing the PCN and types as well as the description of the SDH products exported to India during the POI.

56. M/s ZTE Corporation was informed vide e-mail dated 26th August 2009 that the exports volume as per their response appears to be under-reported when compared to the DGCI&S Data. In the response, the representative of the company stated while preparing the export information, the Company only took into consideration of the export which the revenue has been recognized during POI with its clearance date falling in the POI. In accordance the same principle, as to the export with its clearance date being out of POI or its revenue has not been recognized during POI, for lack of actual price, cost and so on, the Company didn't take into consideration. It was further pleaded that Pursuant to the accounting system of the Company, generally all the revenue under the contract shall be recognized only when all the products of the contract are completely exported, which are the familiar and common practice in this industry. This, they claim is a special circumstance which needs special consideration by the Investigating Authority.

57. It has further been submitted that for the above mentioned cause, may be some exports of part of the total contract wasn't calculated into the response of the Questionnaire, the Company is now preparing this information, and will be submitted shortly.

M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd. China PR

58. As for the confidentiality of the PCNs for the product under investigation and the like products, Fiberhome would advise the following considerations

- i. The functions a SDH product plays, major components it uses and specific design by which it is produced or assembled make the products different from each other, and make them recognizable from other products, what the different codes in PCN reflect is core technology for business in this industry, in addition, the PCN system proposed by the petitioner includes 15 codes which represent in 15 technical characteristics and will indicate how does the exporting producer have made different types of its

- products. It is therefore reasonable to identify the rule of PCN code editing as a company's business secret which are widely protected by rules on intellectual property rights.
- ii. It is noted that the Petitioner has obtained information regarding the PCNs of export from China during POI, if the exporter discloses all its PCNs to the petitioner, the latter will be able to derive, by matching the two sets of PCNs, some key data, such as export price, which are very important for the exporters.
 - iii. Reference is drawn to the non confidential version of the petition whereby the Domestic Industry has claimed that they have the information of all imports through their intelligence and the same has formed basis to work out the Export Volumes and Export Price in the Petition. In view of the forgoing, we submit that if the Domestic Industry has claimed to have (and duly accepted by the Designated Authority at the time of initiation investigation) that all the required information about exports specifications and consequently PCN supplied by the exporters, there is no justification for the Domestic Industry to seek this information from the exporters particularly when they have claimed complete confidentiality on all the PCN produced and sold by them.
 - iv. It is noted that the petitioner has not provided PCN for its own products, and it is not understandable to request for only the exporters to provide same and it is also unreasonable for and unfair for the petitioner to ask for the disclosure. It is further submitted that the present petition for imposition of Anti Dumping Duty on SDH has been filed by the Domestic Industry and they should first themselves prove and abide by the provisions under Rule 7 before making allegations on the submissions made by the Exporters. We reserve our right to make detailed submissions on the excessive use of confidentiality by the Domestic Industry in the non confidential version of the Petition for initiation of Anti Dumping Investigation.

Examination by the Authority

59. The Authority takes note of the submissions on disclosure of PCN details and confidentiality claims by ECI both in respect of the Chinese as well as Israel Company, ZTE and Fibrehome. The Authority, Notes that at least two major producers and exporters who have responded viz. Huwaei and Alcatel have disclosed PCN details in the NCV. Therefore there is no reason for other responding exporters to claim confidentiality on disclosure of PCN details claiming the same to be business sensitive information. The Authority therefore directs these responding exporters to disclose the PCN details in a non-confidential version so that the same can be placed on Public file. The Authority further holds that in case these responding producers / exporters fail to provide the disclosure of PCN's as above in a non-confidential version, the Authority shall consider them as non-cooperative for the purposes of final determination.

60. With regard to the incomplete data on exports to India filed by ZTE Corporation, the Authority holds that the data recognized as having been imported into India is based upon the generation of inward bill of entry for home consumption. In the instant case a no. of export entries are reflected in DGCI&S data which have not been reported by the responding exporter and the claim that accounting system of the Company, generally all the revenue under the contract shall be recognized only when all the products of the contract are completely exported cannot be accepted as the same is not commensurate to the practice being followed by the Authority. Authority, holds that the responding exporter under reported the sales during POI and therefore the data cannot be relied upon for determination at this stage. Therefore for the purposes of provisional determination, the Authority has treated M/s ZTE Corporation as non-cooperative

for the purpose of preliminary findings. A view as to whether the data proposed to be provided a fresh by the company shall be accepted subsequently for final determination shall be taken by the Authority on receipt of the same.

Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Normal Value

Claims made by the Domestic Industry

61. Applicants have claimed that China is a non-market economy. No country has granted market economy country status to China after following detailed evaluation procedure, examination and evaluation. They have further claimed that even China agreed in the accession treaty that WTO Members could use an NME antidumping methodology through December 11, 2016. China has been treated as non-market economy by European Commission and United States in the past three years. European Union and United States are members of World Trade Organization. In India also, the Designated Authority has treated China as non-market economy. The Designated Authority has treated China as non-market economy in practically all the investigations initiated against China after the amendment dated 31st May, 2002. Even after the amendment dated 4th Jan., 2003, the Designated Authority has treated China as a non-market economy.

62. Applicants claimed that producers from Israel are dumping subject goods in India. They have claimed to have determined normal value in Israel on the basis of price paid and payable in the domestic market in Israel. They have claimed that Israel being a part of Mid-east / Europe region, the average selling price of PUC is expected to be even higher than those in Asia and in the absence of any information with regard to actual transaction price in Israel, price determined based upon market research reports has been adopted for determination of normal value.

Examination by the Authority

China PR

Examination of Market economy claims

63. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the above Rules.

64. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

- a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

- b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c) Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- d) The exchange rate conversions are carried out at the market rate

65. The Authority notes that a number of producers and exporters from China PR have responded to the questionnaire pertaining to market economy status and to the exporters' questionnaire, consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption. The questionnaire responses and the market economy responses of the responding producers and exporters were examined. In respect of M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd., M/S ZTE Corporation, M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. and M/S Huawei Technologies Co., Ltd. M/S Hangzhou ECI Telecommunication CO. Ltd the responses have been found to be deficient and there are missing links between the claims made that they are operating under Market economy conditions and actual information available on record. Separate communications are being sent to each of these responding exporters, seeking comments on the observations made by the Authority. In respect of M/S Hangzhou ECI Telecommunication CO. Ltd, it is noted that as per the Article of Association dated ***, Hangzhou eastern ECI Telecom Ltd. Liability company was established as a JV company between Hangzhou Eastern Telecommunication company(Party A) and ECI Telecom Ltd., Israel(Party B). The registered capital of the JV company was US\$ *** million out of which ****% was to be contributed by party A and ****% by party B. Perusal of this AOA (Article ***) reveals that it is taken as an integral part of the "contract "dated *** but the copy of this contract has not been filed in the response. The business license shows registered capital as US\$ *** million where as AOA reflects the same at US\$ *** million. Further as per amended Article Of Association dated ***, it is seen that registered capital was US\$ *** million in which share of party A was ****%. The capital verification report, which is normally prepared in terms of AOA, as and when registered capital / paid-up capital are changed, has not been filed with the response. The AOA were further amended on *** according to which the company becomes wholly foreign owned enterprise. The response does not mention as to for what consideration the share holding of Party A was transferred in favour of party B and process followed in the evaluation of assets. Further as per the response, it is seen that Hangzhou Eastern Telecommunication Company was the producer but the business license of this company was not filed. In the absence of these vital missing links it is not possible for the Authority to grant MET status for the purposes of preliminary determination. The Authority notes that none of these responses from Chinese exporters are flawless and therefore, pending examination of the issues regarding ownership and control, its impact on the cost and prices and business decisions of the company, transformation of ownership from time to time, evaluation of assets, land use rights, the Authority is of the view that all these five producers- exporters from China PR cannot be granted market economy status for the preliminary determination of its Normal Value. However, their submissions regarding Market Economy Claim will be examined in detail during the course of investigation and verification by the Authority. The position in this regard is proposed to be reviewed during the course of investigation, if, upon verification these companies satisfy the MET norms.

Normal Value**China PR**

M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd., Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd. and M/S Huawei Technologies Co., Ltd.

66. Under the circumstances, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the above named Chinese companies and has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure- I to the Rules. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:

- a. On the basis of the price in a market economy third country, or
- b. The constructed value in a market economy third country, or
- c. The price from such a third country to other countries, including India.
- d. If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

67. The Authority indicated, in the Initiation Notification, that the applicant has suggested that subject product is produced and sold in USA and Europe and these countries can be treated as surrogate country for China. The applicant furnished names and addresses of the producers in these countries.

68. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. Since no information with regard prices and costs prevalent in these markets could be accessed and also the responding Chinese companies have made no claim with regard to an appropriate market economy third country, Pending further examination of the issues, for the purpose of preliminary determination the Authority proceeds to provisionally determine the normal value in respect of M/s Fibrehome, M/s Alcatel & M/s Huawei China PR and M/S Hangzhou ECI Telecommunication CO. Ltd on other reasonable basis, in terms of second proviso of para 7 of Annexure 1 to the Rules. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration for all exporters from China PR has been provisionally constructed based on facts available. The Normal Value has been constructed taking into account actual weighted average price of all the major inputs due to non-availability of international price for various components separately for SDH equipments of different types. It is noted that even the domestic industry is sourcing its major components from the international markets. Conversion cost, and SGA expenses of the domestic industry, duly moderated, have been adopted for determination of the normal value. After adding a reasonable profit margin of 5%, normal value has been constructed. The weighted average normal value for the PCNs exported by the Chinese producers working under non-market economy are shown below:

Name of the Company	Nos. of PCN's	Qty (Nos.)	Weighted Avg. Normal Value (USD/No.)
M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	***	***	***
Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	***	***	***
M/S Huawei Technologies Co., Ltd.	***	***	***
M/S Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd	***	***	***

Israel**M/S ECI Telecom Ltd. Israel**

69. The Company has provided information in various appendices, along with Bill of Materials, which has been examined by the Designated Authority. Authority notes that out of 119 PCN are exported to India, only six numbers have been sold in domestic market and seven to third countries. Since all such domestic sales and sales to third countries are profit making, the normal value has been determined based on sales in the domestic market/ third country. The rest of the PCN's have not been sold except to Indian market. Therefore, and cost of production, as per the responding producer / exporter and reasonable profit margin has been taken for determination of normal value. Accordingly, the normal value has been worked out as under:

Name of the Company	Nos. of PCN's	Qty (Nos.)	Weighted Avg. Normal Value (USD/No.)
M/S ECI Telecom Ltd, Israel	***	***	***

Export Price**Responding Exporters from China PR****M/s Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd., China PR**

70. As per response filed with the Authority, they have exported *** PCN Variants to India during POI, comprising of *** Nos. Adjustment claimed on account of Clearance, Inland & Ocean Freight and insurance, Bank Charges, Credit Cost, Packing Cost and VAT as per the revised response filed by them. All the adjustments claimed have been allowed subject to verification, except VAT adjustment which has been claimed @ 0.04% in respect of Hardware alone. Authority has however calculated this adjustment @ 4% of total value including Hardware and Software, again subject to verification. Net export price at ex-factory level in respect of each PCN has been worked out accordingly for comparing the same with the Normal Value at the same level of trade.

M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd. China PR.

71. As per response filed with the Authority, they have exported *** PCN Variants to India during POI, comprising of *** Nos. Out of these *** are cards, and quantity in respect of the same having been mentioned, same have been included for determination of NEP. Adjustments as claimed have been allowed for determination of net export price at ex-factory level in respect of each PCN for provisional measures, subject to verification of the records to establish the said claim of adjustments etc. by the responding exporter

M/S Huawei Technologies Co., Ltd. China PR.

72. As per response filed with the Authority, they have claimed to have exported *** PCN Variants to India during POI, comprising of *** Nos. Out of these *** PCN's are cards no quantity has been mentioned in respect of these ***PCN's. Therefore these have been excluded for the purpose of determination of NEP. Adjustments as claimed have been allowed by the Authority are for preliminary determination and the same are subject to verification by the Authority.

M/S Hangzhou ECI Telecommunication CO. Ltd China PR.

73. As per response filed with the Authority, they have claimed to have exported *** PCN Variants to India during POI, comprising of *** Nos. Adjustments as claimed have been allowed for working out NEP and NEP so claimed has been allowed by the Authority for preliminary determination, subject to verification.

Israel**M/S ECI Telecom Ltd. Israel**

74. As per response filed with the Authority, they have claimed to have exported *** PCN Variants to India during POI, comprising of *** Nos. Adjustments have been claimed on account of Inland Freight, Overseas Freight, insurance, storage, Finance Cost and Warranty. The same has been allowed as claimed for the purposes of preliminary determination, subject to verification.

Dumping margin

75. The Authority has recognized differences in physical and optical characteristics of different types of SDH equipment and has accordingly compared normal value with export price by considering the physical and optical characteristic and configurations of SDH equipments imported against identical specifications. The comparison has been made on the basis of Normal value and export price in respect of each PCN separately and weighted average Normal Value has thereafter been compared with the weighted average NEP for determination of Dumping Margins. The dumping margins so determined are detailed in the table below.

Name of the Company	Weighted Normal Value (USD/No.)	Avg. Value (USD/No.)	Weighted Export Value (USD/No.)	Avg. Value (USD/No.)	Dumping Margin USD/No. (%)
M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	***		***		*** (240% to 250%)
Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	***		***		*** (30% to 40%)
M/S Huawei Technologies Co., Ltd.	***		***		*** (50% to 60%)
M/S Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd	***		***		*** (90% to 100%)
M/S ECI Telecom Ltd., Israel	***		***		Negative

Injury Determination

76. The Authority has noted the views expressed by the interested parties in respect of the injury claims of the domestic industry and examined the mandatory factors for the purpose of provisional injury determination and causal link analysis in these findings.

Submissions by the domestic industry

77. The Domestic Industry has made following submissions on Injury.

- (i) The product under consideration is required by the customers for setting up the optical transmission backbone of their telecom networks. It is a capital goods procurement for them. Given the huge value of investments involved, the customers follow a well laid down system of purchase.

- (ii) Companies such as BSNL, MTNL and RailTel, follow a system of open tendering, whereas private players (such as Bharati, Reliance, Tata Communication etc.) follow a system of closed tenders through a Request For Proposal (RFP) process.
- (iii) In open tenders, bids are invited from all suppliers in closed sealed envelopes, such bids are opened in presence of all participating suppliers and prices quoted by suppliers are announced publicly. In closed tenders, the customers invite quotations, compare the same and thereafter normally place orders based on the best commercial offer (lowest price, credit terms etc.).
- (iv) Price negotiation in both the systems is not ruled out. Such price fixation can be for specified volumes or tentative volumes. Actual shipments however take place over the tenure of the rate contract (of 12-24 months).
- (v) Considering high value of business involved, the petitioner regularly tracks requirement of individual customers and very closely monitors each offer made.
- (vi) Petitioner is reasonably well aware of the procurements made by the customers. Petitioner is reasonably well aware of the procurement decision taken by the customers.
- (vii) Petitioner has consolidated information with regard to various orders won and lost over the injury period based on this market intelligence regularly developed.
- (viii) Various intending suppliers quote irrevocable prices. After this offer, while there is a possibility of further price reduction, there is no possibility of increase in the prices.
- (ix) Designated Authority should focus on the offers made by the Foreign Producers and Indian Producers for assessing injury to the domestic industry. The injury margin should also be determined based on these offers made by the foreign suppliers.

Assessment of import volumes --

78. The Authority has examined information made available by the petitioner from secondary sources, information received from the DGCI&S, information made available by the petitioner from IBIS, information provided by the responding exporters and importers for assessment of import volumes. The Authority has considered information made available by the responding exporters in so far as POI is considered. For previous years, since none of the exporters have provided information in the form and manner prescribed and have provided information for different periods, the Authority is constrained to adopt information contained in the petition.

Assessment of demand

79. Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the domestic producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in following table.

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08	POI annualised vis-à-vis 2005-06
<u>In terms of numbers</u>						
China	***	***	***	***	***	1364%
Israel	***	***	***	***	***	35%
Subject Countries	***	***	***	***	***	240%
Other Countries	***	***	***	***	***	151%
Imports in India	***	***	***	***	***	186%
Sales of Domestic industry as per excise records	***	***	***	***	***	175%

Sales of Other Indian Producers as estimated by the domestic industry	***	***	***	***	***	
Demand	51,308	118,500	81,186	94,027	70,520	183%
In terms of value – Rs. Lacs						
China	***	***	***	***	***	1159%
Israel	***	***	***	***	***	183%
Subject Countries	***	***	***	***	***	334%
Other Countries	***	***	***	***	***	229%
Imports in India	***	***	***	***	***	270%
Sales of Domestic industry	***	***	***	***	***	234%
Estimated Sales of Other Indian Producers	***	***	***	***	***	
Demand	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062	262%

80. Demand for the product under consideration is shown significant increase in terms of both numbers and values. Domestic industry alleged that in spite of significant increase in the demand in the country, they are not able to take advantage of the same because of dumping from subject countries. This allegation of the domestic industry is corroborated as much as the demand has gone up from 100 (2005-06) to 183 (POI), the corresponding sales of the domestic industry could go up to only 175 during the period.

Import volumes and market share

81. With regard to the volume of the dumped imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure-II (ii) of the Anti-dumping rules provides as under: -

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India"

82. Volume of dumped imports from the subject countries is given in following table:-

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April- Dec 08
Subject Countries	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142
Others	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588
Total Imports	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730
Indian Production	9,930	24,337	10,978	17,053	12,790
Indian Consumption	51,308	118,500	81,186	94,027	70,520
Market Share imports					
Subject Countries	31.49%	47.18%	45.19%	41.32%	41.32%
Others	49.15%	32.28%	41.29%	40.54%	40.54%
Subject Countries Imports in relation to Indian Production	162.73%	229.72%	334.20%	229.54%	227.85%

83. The Authority notes that the volume of imports from subject countries has increased significantly. It is noted that whereas the volume of imports from subject countries during POI

(annualized) (when measured in terms of numbers) increased by about 140% over base year 2005-06. Share of subject countries in total Indian consumption of the product increased significantly from 31% to 41% over the injury period. In terms of value, the absolute imports from subject countries have increased significantly by about 234% during POI (annualized) over 2005-06.

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08	POI annualised vis-à-vis 2005-06
Imports in Nos.						
China	2,502	9,959	10,056	34,132	25,599	1364%
Israel	13,657	45,948	26,632	4,724	3,543	35%
Subject Countries	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142	240%
Other Countries	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588	151%
Total Imports	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730	186%
Imports in Value Rs. Lacs						
China	2,461	6,717	14,564	28,500	21,400	1159%
Israel	13,433	30,989	38,570	24,553	18,414	183%
Subject Countries	15,894	37,706	53,134	53,085	39,814	334%
Other Countries	24,805	25,802	48,545	56,791	42,593	229%
Total Imports	40,699	63,508	101,679	109,876	82,407	270%
Indian Production						
Volume	9,930	24,337	10,978	17,053	12,790	170%
Value Rs. Lacs	9,767	16,414	15,898	22,207	16,655	227%
Subject Countries Imports in relation to Indian production						
Volume	163%	230%	334%	228%	228%	141%
Value Rs. Lacs	163%	230%	334%	239%	239%	147%

84. It is seen that there has been significant increase imports from subject countries both in absolute term as well as in relation to production in India.

Imports in relation to consumption in India

85. Volume of dumped imports from the subject countries in relation to consumption in India is given in following table:-

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08	POI annualised vis-à- vis 2005-06
Imports in Nos.						
China	2,502	9,959	10,056	34,132	25,599	1364%
Israel	13,657	45,948	26,632	4,724	3,543	35%
Subject Countries	16,159	55,907	36,688	38,856	29,142	240%
Other Countries	25,219	38,257	33,520	38,117	28,588	151%
Total Imports	41,378	94,164	70,208	76,973	57,730	186%
Imports in Value Rs./ Lacs						
China	2,461	6,717	14,564	28,500	21,400	1159%
Israel	13,433	30,989	38,570	24,553	18,414	183%
Subject Countries	15,894	37,706	53,134	53,085	39,814	334%
Other Countries	24,805	25,802	48,545	56,791	42,593	229%

Total Imports	40,699	63,508	101,679	109,876	82,407	270%
Indian Consumption						
Volume	51,308	1,18,500	81,186	94,027	70,520	183%
Value Rs. Lacs	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062	262%
Subject Countries Imports in relation to Indian Consumption						
Volume	31.49%	47.18%	45.19%	41.32%	41.32%	131%
Value Rs. Lacs	31.50%	47.23%	45.19%	40.19%	40.19%	128%

86. It is seen that imports from subject countries which were only 31.5% during 2005-06 went up to 41.32 % in POI in relation to consumption in India. Authority notes that volume impact of the imports on the domestic industry has been adverse.

Price effect of imports

87. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

88. The Authority notes that each consumer procures SDH equipment meeting its specific requirement. SDH equipment used by a consumer at one station might differ from SDH equipment used at other stations in terms of associated physical and optical properties. In view of the same, for the purpose of assessment of price undercutting, the Authority has considered most closely resembling product type sold by domestic industry and compared the same with imported product type. Wherever there are no identical models, the Authority has considered a model having lower configuration than the imported product in order to ensure that price undercutting was not overstated. After determining price undercutting for individual PCN exported, the Authority has determined weighted average price undercutting for the responding exporter after considering associated volumes. It is seen that the price-undercutting margin are quite significant.

89. In this regard, Authority examined price undercutting separately for each model (PCN). Wherever the domestic industry has not offered identical model, the Authority has considered comparable lower model offered by the domestic industry. It is seen that the landed price of imports for the responding exporters are significantly lower than the selling price of the same equipment offered by the domestic industry, resulting in significant price undercutting. In fact, wherever the domestic industry has not offered identical model and comparison has been made with comparable lower model, it is seen that the landed price of imports are lower than the selling price of the domestic industry. While the domestic industry argued that its selling prices must be adjusted upwards in these cases, it is observed that the extent of price undercutting was significant even without such an adjustment.

90. Petitioner claimed that it has been forced to lower its prices in order to continue to get business. Resultantly, the domestic industry has been gradually lowering its prices, far beyond justified levels in view of low & dumped prices offered by the subject exporters. Petitioner also claimed that the prices offered by the foreign producers for supply of the same equipment in subsequent orders have been materially lower than the prices offered in the past. In other words, each successive price offer for supply of the same equipments has been at materially lower prices. Petitioner further argued that whereas the petitioner suo-moto follows a practice of offering lower

prices each successive year to its clients for the same equipment, the price reduction offered by the foreign producers are too significant and too steep. Given the small size of the market [there is limited and known number of suppliers], petitioner further claimed that activities of each of the supplier and consumer get tracked by all concerned. Therefore, low prices offered by the Foreign Producers not only result in loss of business in that account, but also, the same has benchmarking impact on all subsequent offers that the domestic industry makes. Thus, injury to the domestic industry from such loss of business must be seen not only in one account where the domestic industry loses sales, the same must be seen in all other accounts where the domestic industry thereafter is forced to reduce the prices to prevent the dumping.

91. In order to determine whether imports for the product under consideration are suppressing or depressing the prices of product under consideration, the Authority considered the trends in cost of sales and sales revenue for the domestic industry. The relevant information is given below:

Rs. Lacs	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08
Cost of sales	***	***	***	***	***
Indexed	100	144	171	294	294
Increase over previous year		***	***	***	
Sales revenue	***	***	***	***	***
Index	100	139	172	234	234
Increase over previous year		***	***	***	

92. It is seen that the increase in cost of sales in 2006-07 was higher than increase in sales revenue. Thereafter, in 2007-08, the increase in cost of sales was slightly lower than increase in sales revenue. However, in period of investigation (annualized), increase in the sales revenue was far lower than increase in cost of sales. Whereas sales revenue increased only by 36% during POI over 2007-08, cost of sales increased by 72% over the period. It is thus clear that imports were suppressing/depressing the price of domestic industry in the market.

Economic parameters of the domestic industry

93. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Petitioner submits that examination of performance of the domestic industry would reveal that the domestic industry has suffered material injury. Further, the domestic industry is threatened with material injury, should the present condition continue, as discussed in detail here in under:

Capacity and capacity utilization:

94. Petitioner claimed, core of production in this industry is in design and development of the product. The actual process of manufacturing and extent thereof can be in house or outsourced depending on requirement. The petitioner claimed that it can meet the entire Indian demand without any addition to plant and machinery, since producers in this industry leverage the capacities of Electronic Manufacturing Services partners, who in turn have enough capacities to meet the next 10 years requirements of India. In other words, capacity and capacity utilization must be seen in terms of intellectual property and ability of the company to deploy qualified personnel to carry out necessary design and development and manage its global supply chain. On this account, the petitioner has sufficient capacity to meet the Indian demand. In view of the same, petitioner claimed that capacity and capacity utilization may be considered irrelevant parameter in the present case.

95. Petitioner also claimed and no interested parties disputed that production of the product under consideration is extremely peculiar in as much as producers globally are increasingly concentrating on basic research, design & development. Further, petitioner claimed that capacity to produce is not an appropriate parameter in the fact and circumstances of the present case as the manufacturers decide to outsource part production activity depending on a number of factors.

Production and sales volumes

96. Production and sales volumes of the domestic industry moved as shown below:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 – Annualized	April-Dec 08
Production (Nos.)	***	***	***	***	***
Indexed	100	203	117	175	175
Domestic Sales (Nos.)	***	***	***	***	***
Indexed	100	203	117	175	175

97. It is seen that sales and consequently production of the domestic industry shows increasing trend over the injury period. Petitioner claimed that this was a natural outcome of three factors – (a) petitioner commenced production & sale of its new STM-1, STM-4, STM-16 products that enhance the range of its products (b) petitioner has gained additional volumes due to superior technology and support that is appreciated by Indian customers (c) the market for telecommunication equipment in India has seen unprecedented growth in India - thanks to the telecommunication boom and the technological development in telecommunication sector. This was more than envisaged by the petitioner while setting up its facilities and its business plan, and additional investments were made in the company from time to time to support this. In fact, petitioner had envisaged much higher level of operation that could be achieved so far. Petitioner claimed that its production levels in fact have been lower than what it should have been. The reason for sub-optimal performance is the significant reduction in prices by Chinese/Israel suppliers.

98. In view of increase in production & sales and claims of the petitioner, the increase in production was compared with increase in demand. It was seen that even when production of the domestic industry has increased over the injury period, increase in the demand of the product under consideration was far higher than the increase in production. The domestic industry had alleged that imports have taken over significant market opportunities that were available to the domestic industry. The authority thus notes that production of the domestic industry has suffered

because of dumping in as much as the domestic industry has been prevented from increasing production to the extent it should have had in the absence of dumping.

Market Share:

99. Petitioner has claimed, despite the fact that the petitioner is India's first optical networking product company which is innovating and creating significant Intellectual property, the market share of domestic industry has not increased. The same has, in fact, declined. Whereas the petitioner had expected to increase its market share by introduction of new products to expand its range, the market share of the petitioner has declined over the years but because of presence of dumped imports in the market.

100. Market share of the domestic industry was determined in respect of its domestic operations. The verified information showed as follows:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08
Demand/ Consumption in India					
Volume	51,308	1,18,500	81,186	94,027	70,520
Value Rs. Lacs	50,461	79,829	117,574	132,083	99,062
Sales of Domestic industry					
Volume	***	***	***	***	***
Indexed	100	203	117	175	175
Value Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Indexed	100	138	172	233	233
Market Share of Domestic industry					
Volume	***	***	***	***	***
Indexed	100	88	74	96	96
Value	**	***	***	***	***
Indexed	100	87	74	89	89

101. It is seen that the market share of domestic industry has come down during period of investigation both in terms of volume and value in comparison to the base year.

Factors affecting prices:

102. As stated before, landed price of imports being offered by Foreign Producers are significantly below the selling price of the domestic industry. As a result of significant price difference between the imported product price and domestic industry price, consumers have switched over part of their demand to the imported product. Further, the domestic industry has been forced to reduce its prices not only in subsequent supplies to the same customer, but also supplies to other customers in the market as well.

103. The domestic industry claimed, there is dramatic decline in the prices offered by Chinese suppliers. As a result of continued competition from foreign suppliers and loss of business, the

domestic industry has been lowering its prices with every successive offer. The imports are therefore, clearly having significant price depressing effect in the Indian market.

Profit/Loss

104. Petitioner claimed that profits earned by the domestic industry from production and sale of the product under consideration in the domestic market declined over the injury period. So significant has been decline in the profits over the years that the petitioner has suffered financial losses during the POI in its domestic business.

105. Profit/loss of the domestic industry was determined in respect of its domestic operations. The verified information showed as follows:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08 - Annualized	April-Dec 08
Profit/Loss Rs./ Lacs					
Domestic	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	(100)	(207)	(162)	(964)	(964)
As per annual report	(***)	***	***	(***)	(**)
Indexed	(100)	64	165	(14)	(14)
Sales Value Rs./ Lacs					
Domestic	***	***	***	***	***
Indexed	100	138	172	233	233
As per annual report	***	***	***	***	***
Indexed	100	187	302	352	352
Profit/Loss as % of Sales					
Domestic	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	(100)	(149)	(94)	(412)	(412)
As per annual report	(****%)	****%	****%	(****%)	(****%)
Indexed	(100)	34	55	(4)	(4)

106. It is seen that the sales revenue of the domestic industry remained consistently below the cost of sales resulting in financial losses in respect of domestic operations. Further, loss has in percentage of sales revenue increased substantially from ****% in 2005-06 to ****% in the period of investigation. It is thus seen that the domestic industry was suffering significant financial losses, which increased significantly over the injury period.

107. Since the petitioner has significant export activities, its profits in combined operations in domestic and exports continue to be positive. Petitioner claimed that its export profits are at present financing the domestic losses. Petitioner further claimed that no company can survive in the long run on such basis. Dumping has created very adverse position for the domestic industry.

Return on Investments

108. Since basic investments in production of the subject goods is in intellectual property in terms of design and development and skilled/qualified man power, petitioner claimed that the return on investment expressed as a percentage of return on capital employed would not adequately reflect the reasonable returns that this industry can expect. Globally the industry considers profitability in terms of gross margins and the gross margins of the domestic producers in India are significantly lower than the gross margins for their global peers.

109. Return on capital employed was determined in respect of its domestic operations showed as follows:

Rs./Lacs	2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec 08
Capital Employed – Company as a whole				
Net Fixed Assets	***	***	***	***
Indexed	100	180	497	346
Working capital	***	***	***	***
Indexed	100	161	249	336
Capital Employed	***	***	***	***
Indexed	100	162	262	318
Profit before interest and tax	(***)	***	***	***
Indexed	(100)	132	285	55
Return on capital employed - %	(***)	***	***	***
Indexed	(100)	82	109	16
Capital Employed – PUC Domestic				
Indexed	100	120	149	224
Profit before interest and tax PUC domestic	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	(100)	(179)	(60)	(910)
Return on capital employed - %	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	(100)	(149)	(40)	(406)

110. The analysis of trend in return on capital employed showed that the domestic industry has not been able to earn profits throughout the injury period so far as domestic operations are concerned. The negative return on capital employed, which was 100 in 2005-06 went up further to over 400 in POI. For the company as a whole, the domestic industry in the base year made losses. However during 2006-07 and 2007-08, the company earned profits but during POI, the return on capital employed declined significantly to the level of less than 2%. The company on its all operations including exports earns some profits mainly due to export operations. These trends clearly show that the profitability of the domestic industry has suffered adversely.

Cash flow/profit

111. Petitioner claimed that since the domestic industry has significant domestic and export operations, cash flow situation of the domestic industry is not totally reflective of the impact on dumping on cash flow. Therefore, cash profits situation of the domestic industry have been ascertained considering profit before taxes and depreciation. It is seen that domestic industry had negative cash flow through out the injury period. Further, the cash loss increased substantially in the investigation period.

	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Cash Profit – PUC domestic	(***)	(***)	(***)	(***)
Indexed	(100)	(211)	(158)	(688)

Inventories: -

112. The product under consideration is produced only after taking firm order based on detailed specifications and these goods are not kept in inventories.

Employment and Wages

113. Petitioner claimed, one of the major investments is in development of intellectual property in terms of research and development. As stated before, petitioner had anticipated significant market opportunity because of the unprecedented telecommunication boom in the Country. Further, the domestic industry is improving its global presence, which also calls for intensified research & development activities. All this required investment in manpower. Resultantly, manpower deployed and consequently wages paid by the domestic industry has increased over the years, as would be seen from the table below.

SN		2005-06	2006-07	2007-08	April- Dec 08
	Number of employees				
(a)	Research & development	***	***	***	***
	Indexed	100	151	247	324
(b)	All other activities	***	***	***	***
	Indexed	100	139	178	211
(c)	Gross employment	***	***	***	***
	Indexed	100	145	215	272
2	Wages				
(a)	Research & development (Rs./Lacs)	***	***	***	***
	Indexed	100	181	281	226
(b)	All other activities (Rs./Lacs)	***	***	***	***
	Indexed	100	166	271	260
(c)	Gross employment (Rs./Lacs)	***	***	***	***
	Indexed	100	174	276	242

114. Petitioner claimed that it is not possible to reduce the employment, as any such effort would imply a process of permanent decline of the domestic industry. The intent of the foreign producers is very clear – to eliminate Indian industry in this important product segment. The petitioner claimed that the product under consideration was developed by them in this Country and India joined select few countries in the world having capability and capacity to produce this high technology product. The Telecom growth in India has created a huge demand for the product under consideration. Elimination of Indian Producer can provide not only huge market opportunity to the foreign producers in India, but also would eliminate competition to them in global market. Present dumping is therefore likely to have very significant adverse impact on employment and wages, as India is trying to move up the value chain and create a talent pool of technologists who can create high-value, intellectual property and products.

115. Petitioner further claimed that the Govt. of China was supporting its telecom equipment manufacturing industry in a variety of ways, which includes huge soft loans.

Productivity:

116. Productivity of the domestic industry has been measured in terms of production per employee, expressed in number and value of SDH equipments produced.

SN		2005-06	2006-07	2007-08	April-Dec08
1	Production per employee				
(a)	Number of equipment Domestic Industry	***	***	***	***
	Indexed	100	140	54	48
(b)	Value of equipment Domestic Industry (Rs./Lacs)	***	***	***	***
	Indexed	100	97	81	66

117. It is seen that the productivity of the domestic industry has improved. In spite of improvement in productivity, however, price parameters have deteriorated significantly.

Ability to raise funds:

118. Petitioner claimed that investments in plant and machinery are not a critical factor in the present case. In fact, funds requirements in this industry are more on account of working capital than in fixed assets. Ability of this industry to raise funds may, therefore, seriously be affected with the present level profitability of the domestic industry.

Conclusion on material injury

119. Having regard to the information made available by various interested parties and preliminary determination conducted, the Authority provisionally concludes that subject imports have increased in absolute terms and in relation to production & consumption in India. There is significant decline in the import price over the injury period. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. Imports are depressing the prices of the product under consideration in the market. Performance of the domestic industry deteriorated in terms of profits, market share, return on investment, cash flow, inventories and growth. Even though volume of production and sales increased over the injury period, the domestic industry lost significant business opportunities to sell their products in the market. Decline in profits, return on investments and cash flow is in spite of significantly improved performance on export front. Employment, productivity and wages have improved. However, the improvement therein far outweighs the deterioration in other parameters. The deterioration in the performance during the current period is quite significant and material.

Causal link

120. Having examined the existence of material injury and volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic in terms of its price undercutting, price underselling and price suppression, and depression effects the Authority has also examined whether other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti Dumping could have contributed to injury to the domestic industry. Therefore, the following parameters have been examined:

- a) Imports from Third Countries: - Imports from countries not under investigation are either insignificant or at prices higher than the import prices from the subject countries and therefore, do not affect the prices in the domestic industry;
- b) Contraction in Demand: - Demand for the subject goods have increased substantially during the injury examination period. Therefore, possible contraction in demand cannot be attributed to the injury to the domestic industry.

- c) Pattern of consumption: - No significant change in the pattern of consumption has been alleged by any interested party.
- d) Conditions of competition: - The goods are freely importable. The applicant is the major producers of the subject goods and account for almost 100% of the domestic production. Therefore, domestic competition could not be attributed to the injury to the domestic industry. No other evidence of conditions of competition or trade restrictive practices has been brought to the knowledge of the Authority.
- e) Developments in technology: - There is no allegation of significant changes in technology which could have caused injury to the domestic industry.
- f) Export performance of the domestic industry: - There is no evidence on record to show that exports of the DI have any impact on its performance.
- g) Productivity: - Productivity of the domestic industry has improved in terms of total output. Therefore, this cannot be attributed to the injury of the domestic industry.

121. The non-attribution analysis as above shows that no other factor other than the dumped imports has affected the domestic industry.

Factors establishing causal link:

122. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from subject countries. Therefore, the causal links between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- a. The dumped import prices and consequently the landed price of imports from the subject countries steeply declined, resulting in significant price undercutting. As a direct consequence, the domestic industry was forced to reduce the prices.
- b. Reduction in the selling prices by the domestic industry adversely affected the profits, cash flow and return on investments of the company.
- c. Even though the domestic industry responded to decline in import prices, significant positive price undercutting resulted in increase in market share of imports from the subject countries. As a direct consequence, market share of the domestic industry declined.
- d. In spite of increase in demand and reduction in selling prices by the domestic industry, market share of the domestic industry declined due to significant reduction in landed price of imports. This retarded the growth of the domestic industry.
- e. The significantly low prices being offered by the foreign producers have prevented the domestic industry from increasing its production and sales to the level it could have in the absence of dumping.

123. Therefore, the Authority provisionally concludes that the domestic industry suffers material injury and the injury has been caused by the dumped imports from the subject countries/territories.

Magnitude of Injury and injury margin

124. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The comparison has been done by determining the non injurious price for the model imported in India. Separate comparison has been done and injury margin determined for each model imported. Thereafter, the weighted

average injury margin has been determined considering the associated import volumes. The injury margins have been worked out as follows:

Country	Exporter	Injury Margin Rs Per Pc	Injury Margin %
China PR	M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	***	250% to 260%
	Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	***	25% to 35%
	M/S Huawei Technologies Co., Ltd.	***	50% to 60%
	M/S Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd.	***	95% to 105%
Israel	M/S ECI Telecom Ltd., Israel	***	Negative

Conclusions

125. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding the authority provisionally concludes that:

- The subject goods have entered the Indian market from the subject countries at prices less than their normal values in the domestic markets of the exporting countries;
- The dumping margins of the subject goods imported from the subject countries are substantial and above de minimis;
- The domestic industry has suffered material injury and the injury has been caused to the domestic industry both by volume and price effect of dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Indian industry's interest & other issues

126. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

Recommendations

127. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted a preliminary investigation into dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down and having provisionally established positive dumping margin against the subject countries, and having concluded that the domestic industry suffers material injury due to such dumped imports the Authority is of the opinion that imposition of provisional measure is required to prevent injury being caused to the domestic industry during the investigation period.

128. Therefore, Authority considers it necessary and recommends provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder:

129. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, provisional antidumping duty as indicated in Col 9 of the duty table below, which shall be as a percentage of CIF value of imports, is recommended to be imposed from the date of notification, to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries/territories.

Duty Table

S. No.	Sub-Heading	Description	Country Of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	851762	"Complete SDH Equipment including in CKD / SKD and including its parts and components which have a dedicated use for the equipment."	China PR	China PR	M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	M/S Fibrehome Telecommunication Technologies Ltd.	236%	% of CIF Value of Imports
2	-DO-	-DO-	China PR	China PR	Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co. Ltd.	29%	% of CIF Value of Imports
3	-DO-	-DO-	China PR	China PR	M/S Huawei Technologies Co., Ltd.	M/S Huawei Technologies Co., Ltd.	50%	% of CIF Value of Imports
4	-DO-	-DO-	China PR	China PR	Any other combination than as at Sl. 1, 2 and 3 above	Any	236%	% of CIF Value of Imports
5	-DO-	-DO-	China PR	Israel	M/S Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd	M/S ECI Telecom Ltd., Israel	93%	% of CIF Value of Imports
6	-DO-	-DO-	China PR	Israel	Any other than combination as at Sl.No.5 above	Any	236%	% of CIF Value of Imports
7	-DO-	-DO-	China PR	Any other than Israel	Any	Any	236%	% of CIF Value of Imports
8	-DO-	-DO-	Any	China PR	Any	Any	236%	% of CIF Value of Imports
9	-DO-	-DO-	Israel	Israel	M/S ECI Telecom Ltd., Israel	M/S ECI Telecom Ltd., Israel	Nil	% of CIF Value of Imports
10	-DO-	-DO-	Israel	Israel	Any other than combination as at Sl.No. 9 above	Any	37%	% of CIF Value of Imports
11	-DO-	-DO-	Israel	Any other than Israel	Any	Any	37%	% of CIF Value of Imports
12	-DO-	-DO-	Any	Israel	Any	Any	37%	% of CIF Value of Imports

Further Procedures

130. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final finding;
- (b) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the dispatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty (40) days from the date of publication of these findings;
- (c) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
- (d) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

R. GOPALAN, Designated Authority